स्वदेशी आन्दोलन

दत्तोपंत ठेंगड़ी

स्वदेशी ही समाधान

8 जुलाई, 2002, जोधपुर

स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना

स्थापना पूर्व विरोध :

स्वदेशी जागरण मंच यह नाम अभी सब लोग जानने लगे हैं । किन्तु इसका ग्रह योग कुछ ऐसा रहा कि इसके स्थापना के पूर्व से ही इसका विरोध होता रहा । मैं बंगाल में गया था, वहाँ भाषण में कहा था कि हम स्वदेशी जागरण मंच शुरू करने वाले हैं । प्रेस में भी वह भाषण छपा था, परन्तु कम्यूनिस्टों ने प्रतिक्रिया प्रकट की, अरे यह संघ वाले हैं, आर.एस.एस. वाले हैं, इनको देश और स्वदेशी का क्या पड़ा है, इनको पैसे दिए होंगे उद्योगपतियों ने । काहे के लिए पैसे दिए होंगे कि तुम स्वदेशी का प्रचार करो, विदेशी का बहिष्कार करो और इसके कारण विदेशी माल जब स्वदेशी मार्केट से पूरा हट जाएगा, फिर हम लोगों को विदेशी कॉम्पीटीटर न होने के कारण उपभोक्ताओं का, ग्राहकों का, अनाप-शनाप शोषण करना हमारे लिए सम्भव होगा । चाहे जितना मुनाफा हम कमा सकेंगे, इसीलिए उद्योगपतियों ने इनको पैसा दिया है ।

बाजार भाव सम्बन्धी नीति :

इसके तीसरे ही दिन स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना हुई उसमें कुछ प्रस्ताव पारित हुए कि आज हम स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना कर रहे हैं, जो इसका उद्देश्य पूरा होने तक काम करता रहेगा । और उसमें एक प्रस्ताव पारित किया कि मार्केट में आने वाली हर वस्तु की कीमत "कॉस्ट ऑफ प्रॉडक्शन” उत्पादन खर्चा उस पर लिखा जाना चाहिए । उत्पादन खर्चा, लागत खर्चा के सम्बंध में ऐसा है

कि हमारे शास्त्रों मे मूल्य नीति (प्राइस पॉलिसी) दी गई है । जिस समय ग्रीस में अरस्तू (एरिसटोटल) मूल्य नैतिक है या अनैतिक इसकी चर्चा कर रहे थे उस समय हमारे यहां प्राइस पॉलिसी निश्चित हुई थी । "येनव्ययेन स्वयंसिद्ध तदव्यस्तस्य मूल्यकम् "कि इसका वास्तविक मूल्य क्या है? येनव्ययेन स्वयंसिद्ध" "कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इस द रियल प्राइस", लागत मूल्य आधारभूत मूल्य है । किन्तु रियल प्राइस हमेशा मिलती है कि नहीं, कभी कम मिलती है कभी ज्यादा मिलती है किस आधार पर? "सुलभ: सुलवातच्य अगुणत्व गुणसोस्येहे, यथां कामानपदार्थानाम अरघम् हिनाधिकमभवेत", मूल्य कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है काहे के आधार पर "सुलभ: सुलवातव्य", वो सुलभ और दुर्लभ यानि प्लेन्टी और स्केयरसिटी, "अगुणत्व गुणसोस्येह" उपयोगिता और अनुपयोगिता, यूटिलिटि और नॉनयूटिलिटि अर्थात् डिग्री ऑफ अवेलेबिलिटी और डिग्री ऑफ यूटिलिटि इसके आधार पर कम- अधिक होता है, यह प्राइस पॉलिसी हमारे यहाँ पहले से थी । हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया कि मार्केट में आने वाली कोई भी वस्तु, चाहे देशी उद्योगपति की हो या विदेशी उद्योगपति की हो ' उसकी कॉस्ट ऑफ प्रॉडक्शन घोषित होनी ही चाहिए । इसमें क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अब घोषित होती है, उत्पाद पर लिखी रहती है तो फिर अनाप शनाप मुनाफा नहीं कमा सकते । हाँ, कुछ प्रोफिट मार्जिन रहनी चाहिए यह तो सभी जानते हैं, प्रोफिट मार्जिन यथोचित (रिजनेबल) होनी चाहिए । लेकिन आज जो होता है कि चार रूपये की चीज चार सौ रूपये में बेची जाती है ऐसा नहीं हो सकेगा । तो यह हमने लागत मूल्य (उत्पाद में लगा खर्च) घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया उसके बाद कम्यूनिस्टों की तूती बन्द हो गयी । उनको पता ही नहीं था कि हमारे शास्त्र में कुछ (उपादेय) है उन्होंने शास्त्र पढे ही नहीं थे, और इसीलिए वो निन्दा कर रहे थे, किन्तु उनका बोलना बन्द हो गया ।

स्वदेशी के प्रति अन्य आपत्तियाँ :

स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना होने वाली थी, उसके पिछले दिन हमारे मित्र हमारे पास आए । कहा- ठेंगड़ी जी स्वदेशी जागरण मंच शुरू करने वाले हैं, तो हमने कहा "हाँ" । उन्होंने कहा "माफ करें लेकिन नहीं करेंगे तो अच्छा होगा ।"

हमने कहा "क्यों?। उन्होंने कहा '' आप हमारे हैं सब लोग जानते हैं, पर आप ही स्वदेशी की बात करेंगे, तो हमारी पोजीशन बहुत खराब हो जाएगी । लोग कहेंगे कि दुनिया 21 वीं शताब्दी की तरफ जा रही है, ये लोग हिन्दुस्तान को 21वीं शताब्दी में ले जाना चाहते है ।"

सॉफिस्टिकेटिड लोगों के लिए स्वदेशी कैसे?

और आप जानते हैं वह लीडर थे, बोले "हमारे कानस्टीट्यून्सी (निर्वाचन क्षेत्र) में बहुत सोफिस्टिकेटिड लोग रहते हैं, उनको हम कहे कि साहब कोलगेट नहीं और प्रोमिस या और कुछ इसका इस्तेमाल करो, तो हमको हँसेगे । "मैंने कहा कि ऐसा है '' आपकी कांस्टीटयून्सी का सबसे ज्यादा सोफिस्टीकेटिड आदमी कौन है जरा सोचिए, मैं जानना चाहता हूं । "पंडित मोतीलाल जी नेहरू उस समय के हिन्दुस्तान के सबसे ज्यादा सोफिस्टीकेटिड आदमी माने गए थे । ऐसा प्रख्यात था कि उनके कपड़े पेरिस से धुलकर आते थे, उनसे ज्यादा सोफिस्टीकेटिड आदमी उस समय कोई नहीं था । उनके शरीर पर पूज्य महात्मा गांधी ने खद्दर चढ़ाई तो मोतीलाल जी जिनके कपड़े पेरिस से धुलकर आते थे, उनके शरीर पर वे खद्दर कैसे चढ़ा सके? और मोतीलाल नेहरू से ज्यादा सोफिस्टीकेटिड आदमी आपके कॉन्सटीट्यून्सी में कोई है क्या? तब बोले "वो तो नही है" ।

विदेशी का बहिष्कार नकारात्मक?

और बोले, "एक और प्रार्थना है ।", "क्या है? ।" उन्होंने कहा कि बहिष्कार शब्द बड़ा नेगेटिव (नकारात्मक) दिखता है, यह इज्जतदार शब्द नहीं है, यह नेगेटिव शब्द तो आप छोड़ दीजिए । हमने कहा कि आपके कॉस्टीट्यून्सी में बहुत इज्जतदार लोग दिखाई देते हैं, लेकिन आपको मालूम है क्या कि 1906 में कलकत्ता में जब कांग्रेस हुई थी, उस समय अध्यक्ष दादा भाई नारोजी ने चतुसूत्री दी थी : स्वराज्य, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी और बहिष्कार । तो दादा भाई नारोजी से ज्यादा सोफिस्टीकेटिड आदमी आपकी कॉन्स्टीट्यून्सी में कितने हैं जरा बताइए?

स्वदेशी के लिए दृढ़ विश्वास आवश्यक :

फिर हमने उनको कहा कि दिकत ये नहीं है (कि लोग सोफिस्टिकेटिड हैं), तुमको ऐसा कन्विकशन नहीं है और इसके कारण लोगों को बताना, तुम्हारे लिए कठिन हो जाता है । तो प्रारम्भ से ही स्वदेशी के बारे में आपत्तियाँ, विरोध आते गए ।

स्वदेशी की अवधारणा :

आखिर स्वदेशी की अवधारणा क्या है? ऐसा है कि 12-13 साल पहले की बात है जिस समय जापान अमेरिका के प्रभाव क्षेत्र में था, आज नहीं है, आज बराबरी का है, लेकिन उस समय प्रभाव में था । उस समय केलीफोर्निया में बहुत संतरे हुए । तो अमेरिका ने जापान को कहा कि आपके यहाँ महिलाओं को संतरे बहुत पसंद आते हैं, तो हमारे संतरे आपकी मंडी में भेजेंगे । जापान ने कहा कि आपके संतरे भेजने की आवश्यकता नहीं है । किन्तु अमेरिका ने कहा कि नहीं हम भेजने ही वाले हैं । उस समय जापान को मानना पड़ा । जापान की मंडिया अमेरिकन संतरे से भर गई । लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि सभी मंडियों में बहुत संतरे होते हुए भी एक भी संतरा बेचा नहीं गया, पूरे जापान में । यह बात सही है कि जापानी महिलाओं को संतरे बहुत पसन्द है-, तो भी एक भी संतरा बेचा नहीं गया, इसका नाम स्वदेशी है ।

कुछ 15-16 साल पहले ग्रेट ब्रिटेन की महारानी ने सोचा कि भई ब्रिटेन की जो कार है वो ज्यादा सुविधाजनक नहीं है, उससे जर्मनी की कार ज्यादा सुविधाजनक है, तो हम जर्मनी की कार खरीदेंगे । यह, बात फैल गई, लोगों ने विरोध किया । लोगों ने कहा कि महारानी साहिबा आप हमारा प्रतीक है, कॉन्स्टीट्यूशनल मोनार्क हैं, आप हमारे प्रतिनिधि भी हैं, आप ही अगर देशी कार छोड़कर विदेशी कार में जायेंगे, तो हमारे देश की नाक कट जाएगी । आपको ऐसा नहीं करना चाहिए । महारानी को जर्मन कार नहीं लेने दी गई, ब्रिटिश कार में ही उनको प्रवास करना पड़ा ।

अब देखिए कि विएतनाम के प्रेसिडेंट हो-ची मिह्न भारत में आए थे । जैसे ही वो पालम एयरपोर्ट पर हवाई जहाज से उतरे, तो उस समय लोगों को परमिशन दी गई थी कि वो हवाई जहाज तक जा सकते हैं, तो पत्रकार (प्रेस कारेसपोन्डेंट)

हवाई जहाज तक गए । वो जब उतर रहे थे, तो कुछ पत्रकारों ने देखा और उनको आश्चर्य हुआ कि उनकी पेंट को यहाँ सिलाई थी, सिलाई थी का मतलब है कि वो फट गई (ऊपर मरम्मत हेतु सिलाई) होगी, तो बाद में लोगों ने पूछा कि आप तो एक राष्ट्र के राष्ट्रपति हैं, आपकी पेन्ट ऐसे फटी हुई, सिलाई हुई ऐसी आपकी पेन्ट क्यों हैं, उन्होंने जवाब दिया ' 'माई कन्ट्री कैन अफोर्ड ओन्ली दिस मच '', यह स्वदेशी है ।

गांधी इरविन पेक्ट के समय चर्चा चल रही थी । दोपहर में चाय का समय था, वाइसराय साहब के लिए चाय आई, गांधीजी के लिए नींबू पानी आया । वाइसराय देख रहे थे कि गांधीजी क्या करते हैं । उन्होंने अपने जेब में से एक पुड़ी निकाली, और ऐसे आराम से खोलकर नींबू पानी में डाल दिया । वाइसराय साहब ने पूछा कि "यह क्या है? '' गांधीजी बोले कि '' आपके नमक कानून का उल्लंघन करते हुए मैंने जो नमक बनाया था, उस नमक की पूड़ी मैं इसमें डाल रहा हूं”, यह स्वदेशी है ।

तो स्वदेशी, यह भावना है, केवल आर्थिक बात नहीं है, और इस भावना के आधार पर ही स्वदेश ऊपर जा सकता है और इसीलिए पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने भारतीय जनसंघ के विजयवाड़ा अधिवेशन में जो प्रिंसिपल्स एण्ड प्रोग्राम दिया था, उसमें प्रमुख बात रखी थी, राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता (सेल्फ रिलाएंस)। यह ठीक है कि एकदम सम्पूर्ण आत्मनिर्भरता नहीं आ सकती, कभी-कभी विदेशों से भी लेन-देन करनी पड़ेगी, लेकिन यह लेन-देन बराबरी के नाते होनी चाहिए इक्वल फुटिंग पर होनी चाहिए । वो हमको डिक्टेट करें और हम उनके सामने आत्मसमर्पण करें ऐसा नहीं, बराबरी के नाते होना चाहिए । यह बात पंडित दीनदयाल जी ने कही थी ।

स्वदेशी मंच की सरकार के प्रति भूमिका :

अभी स्वदेशी जागरण मंच के बारे में तरह-तरह के गलत ख्यालात प्रचलित हैं । एक इंग्लिश न्यूज पेपर ने ऐसा लिखा था कि क्या स्वदेशी जागरण मंच आज के सरकार के लिए विपक्ष (ओपोजिशन पार्टी) की भूमिका करना चाहती है । तो

सरकार के विषय में हमारी भूमिका क्या है? यह प्रश्न उपस्थित हुआ था । स्वदेशी जागरण मंच गैर राजनीतिक (नॉन पोलिटिकल) है । हमारे यहां संविधान है, संविधान के अन्तर्गत चुनाव होते हैं, और चुनाव में निर्वाचित जो भी सरकार होगी किसी भी पार्टी की रहे, उसे राष्ट्रीय सरकार हम मानते हैं और राष्ट्रीय सरकार के साथ हमारा रूख क्या है? तो किसी भी पार्टी की सरकार रहे, सभी सरकारों के साथ हमारा एक ही रूख रहेगा और वो क्या है? को-ऑपरेशन । रिस्पोन्सिव को-ऑपरेशन का मतलब होता है, कि किसी भी पार्टी की सरकार हो (हम पार्टी की फिक्र नहीं करते), किन्तु सरकार की नीति यदि स्वदेशी के अनुकूल रहेगी तो स्वदेशी जागरण मंच सरकार का समर्थक होगा, स्वदेशी के प्रतिकूल रहेगी या विरोधी रहेगी तो स्वदेशी जागरण मंच सरकार का विरोध करेगा। इस तरह से उनकी पॉलिसी क्या है यह देखकर हम समर्थन या विरोध तय करते हैं, कौन सी पार्टी पॉवर में है यह देखकर हम तय नहीं करते ।

उपनिवेशवाद का पतन, नव -उपनिवेशवाद का अभ्युदय

अब देखिए भारत सरकार ने पिछले दशक से कुछ गलत नीति को स्वीकार किया । लोगों के भी ध्यान में एकदम नहीं आया इसका कारण था । आज जो नीतियाँ चल रही हैं, विदेशियों की, लोग सोचते हैं कि उनका प्रारम्भ अप्रेल 1948 में जब "जनरल एग्रीमेन्ट ऑन टैरिफ एण्ड ट्रेड" (गैट) निर्माण हुआ तबसे यह नीति बनी ऐसा लोग सोचते हैं । वास्तव में ऐसा नहीं है । दूसरा महायुद्ध समाप्त हुआ 6 जून 1946 को । जनरल आइसन हावर की सेनाएं यूरोप महाद्वीप पर आ गयी, तय हुआ कि हिटलर हारने वाला है । मित्र राष्ट्रों की विजय होगी । तभी से वहाँ के लोगों ने सोचना शुरू किया । हमारे यहाँ तो राजनेता केवल कल के चुनाव की ही बात सोचते हैं, उन्होंने बहुत दूर की बात सोची । क्या सोचा? उन्होंने. सोचा कि हिटलर तो हार जाएगा, हमारी विजय भी होगी, लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति ऐसी है कि हमारे अधीन जो देश है, (क्योंकि सारे साम्राज्यवादी थे, क्या इंग्लैण्ड, क्या अमेरिका, क्या फ्रांस, सभी साम्राज्यवादी थे) हमारे अधीन जो उपनिवेश (कॉलोनीज) है, उनको स्वातन्त्रय देना हमारे लिए बाध्य हो जाएगा क्योंकि उनको अपने कब्जे में रखना हमारे लिए सम्भव नहीं है । उनको स्वातन्त्रय देना पड़

जाएगा किन्तु उसके कारण एक तकलीफ पैदा हुई । साम्राज्यवादी देशों की समृद्धि ऊपर से चकाचौंध करने वाली दिखती थी, किन्तु ये साम्राज्यवादी देश अपने पैरों पर खड़े नहीं थे, अपने उपनिवेशों का शोषण करते हुए वह समृद्ध दिखाई देते थे ।

शोषण का मतलब संक्षेप में मैं बताता हूं - जैसे हमारे विदर्भ में कपास है, जब ब्रिटिश सरकार थी, तो ब्रिटिश सरकार कम से कम कीमत में किसानों से कपास खरीदा करती थी, इंग्लैण्ड ले जाती थी वहाँ मेन्चेस्टर, लेंकाशायर में कपड़ा बनाती थी, कपड़ा बनाने के बाद हिन्दुस्तान में लाती थी और ज्यादा से ज्यादा कीमत में वह कपड़ा बेचा जाता था । वहाँ एक कच्चा माल कम से कम कीमत में लेना, पक्का माल ज्यादा से ज्यादा कीमत में बेचना, इस तरह का शोषण इसके आधार पर वह बड़े समृद्ध दिखते थे । लेकिन उनके सामने सवाल आया, कि देश जब स्वतंत्र हो जाएंगे, तो कौन सा स्वतंत्र देश अपना शोषण करने देने के लिए तैयार हो जाएगा? कोई नहीं तैयार होगा, इसके लिए क्या किया जाए, उनकी मानसिकता बनाई जाए, अभी से प्रोपेगेण्डा शुरू किया जाए ।

पूंजी निवेश, टेक्नोलोजी का दुष्प्रचार :

तो 1948 से नहीं, तभी से (गुलाम बनाए देशों को स्वातन्त्रय देने से ही) प्रोपेगेण्डा शुरू हुआ जिसके कारण हमारे यहां के इंग्लिश एज्यूकेटिड लोगों के मन पर बहुत प्रभाव हुआ । उन्होंने कहा कि कोई भी स्वतंत्र देश अपने पैरों पर खड़ा हो ही नहीं सकता । जब तक हमारा इन्वेस्टमेंट वहाँ नहीं जाता, हमारा पैसा वहाँ नहीं जाता, तब तक वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता । और फिर कहा कि कोई भी स्वतंत्र देश जब तक हमारी टेक्नोलोजी नहीं लेता, हम जब तक टेक्नोलोजी नहीं देते, तब तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता । अब यह इतना प्रचार जो हुआ है, और यह हमारे इंग्लिश एज्यूकेटिड लोगों की विशेषता है कि वहाँ से जो प्रचार होता है उसका सबसे ज्यादा असर इनके उपर होता है, सामान्य लोगों पर इतना नहीं होता, उन्होंने भी मान लिया कि फोरेन इन्वेस्टमेंट के बगैर काम ही नहीं

चलेगा, फोरेन टेक्नोलोजी के बगैर काम ही नहीं चलेगा । वास्तव में यह तर्कशुद्ध भूमिका नहीं है ।

अब देखिए, आज हम कहते हैं पूंजी निर्माण (केपिटल फोर्मेशन) हमारे यहाँ नहीं हुआ और इसके कारण और विदेश से पैसा यहाँ लाना ही पड़ेगा । हम समझ सकते हैं कि कई क्षेत्रों में विदेशी पैसे की आवश्यकता होगी, लेकिन विदेशी पैसा कहाँ लगेगा यह हम तय करेंगे । हमारी आवश्यकता क्या है? अभी दोहा में यह बात आई थी । यूरोपियन देशों ने कहा कि "हमें पूरी दुनिया में राइट टू इन्वेस्ट चाहिए, हम जहाँ चाहे वहाँ, जिस ढ़ंग से चाहे ढ़ंग से, इन्वेस्टमेन्ट कर सकें ऐसा अधिकार हमको मिलना चाहिए ।'' अरे, हमारी सम्प्रभुता का क्या होगा? सोवेरिनिटी का क्या होगा? हमें, हमारे देश में कहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट चाहिए हम तय करेंगे, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, हम तय करेंगे ।

अब यहाँ इन्वेस्टमेंट हो रही है कोका कोला, पेप्सी । क्या हम लोग केवल ये जो पेयजल है, यह भी हम तैयार नहीं कर सकते? टेक्नोलोजी, बड़ी टेक्नोलोजी छोड़िए, किन्तु ये जो पेयजल की होती है, यह भी हम तैयार नहीं कर सकते? इसमें भी हमें फोरेन इन्वेस्टमेंट और फोरेन टेक्नोलोजी चाहिए? सच्ची बात यह है हम जहाँ चाहेंगे वहाँ वह टेक्नोलोजी देने वाले नहीं, जहाँ चाहेंगे वहाँ वे पैसा लगाने वाले नहीं है क्योकि उसमें उनका मुनाफा नहीं है और वो अपनी अपडेट टेक्नोलोजी देकर अपना नुकसान नहीं करेंगे, उनके लिए जहाँ मुनाफा होता है वहाँ वह पैसा लगाएंगे ।

देश के लिये आगे आता रहा है व्यक्ति :

हमारे नेताओं ने कहना शुरू किया - कि साहब, लोग देश के लिए त्याग ही करने को तैयार नहीं तो हम क्या करें, हमको फोरेन के पास जाना पड़ता है । क्या यह बात सही है? राजनेताओं ने कहा कि हर एक आदमी स्वार्थी है, इसके कारण अब फोरेनर्स के पास जाना बाध्य हो जाता हैं । बात ऐसी है कि हर एक आदमी स्वार्थी है यह सच है, किन्तु साथ ही साथ आवश्यकता पड़ने पर आदमी त्याग भी कर सकता है।

अब आप देखिए नेताजी सुभाष चन्द्र बोस दक्षिण एशिया में आए, वहाँ भारत से गए हुए व्यापारी थे, व्यापारी तो अपना मुनाफा कमाने के लिए, स्वार्थ के लिए ही गए थे । लेकिन जब नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने स्वातन्त्रय के नाम से आह्वान किया, तो लोगों ने अपना पैसा ही दिया इतना ही नहीं, तो महिलाओं को अपने अलंकार गहने जो उन्हें बहुत पसन्द आते, वो भी नेताजी के चरणों में उन्होंने समर्पित किए । जो विशुद्ध स्वार्थ के लिए गए थे उन लोगों ने इतना बड़ा त्याग किया, क्यों? क्योंकि लक्ष्य (कॉज) था देश की स्वतन्त्रता और वो आह्वान करने वाला नेताजी सुभाष चन्द्र बोस जैसा पूर्ण स्वार्थत्यागी मनुष्य था इसीलिए लोगों ने पैसे दिए ।

1965 के समय लाल बहादुर शास्त्री ने आह्वान किया, भाई बचत करो और एक दिन एक समय का भोजन छोड़ दो, सब लोगों ने छोड़ दिया । 1962 में चीन के आक्रमण के समय, 1971 में बांग्लादेश की लड़ाई के समय, सब लोगों ने देश के लिए त्याग किया, हमारे मजदूरों ने भी ओवरटाईम न लेते हुए ज्यादा घंटों तक काम किया, ये प्रेरणा कैसे हो सकती है? वास्तव में जिस तरह मनुष्य स्वार्थी है, यह सही है, उसी तरह ठीक आदमी ने ठीक ढंग से यदि आह्वान किया तो लोग त्याग भी कर सकते हैं । किन्तु हमारे नेताओं की बात ऐसी है कि कहाँ कैसे अपील करना है नेताओं को पता नहीं है । जैसे किसी सितार में या किसी वायलिन में एक स्वर निकल सकता है, इसकी जानकारी इनको नहीं है इसीलिए क्या कर रहे हैं सितार को या वायलिन को इधर-उधर, ऐसा- वैसा छेड़छाड़ करते हैं, मालूम नहीं है कि किस तार को कहाँ छेड़ना है, और फिर कहते हैं यहाँ से स्वर निकलता ही नही ।

वास्तव में 1947 में ही, क्योंकि हमारे देश में बचत की प्रवृत्ति बहुत है, अमेरिका में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने आगे के तीन साल का क्रेडिट कार्ड भी खत्म किया है, हमारे यहाँ उससे उल्टा है, गरीब से गरीब आदमी भी थोड़ा सा पैसा बचाता है थोड़ा सा सोना बचा लेता है, जमीन में गाढ़कर रख देता है ' बचत की प्रवृत्ति है और पहले से भी आह्वान किया होता कि स्मॉल सेविंग्स माने बचत यह देश के लिए करनी है, लोग अवश्य करते और पूंजी निर्माण (केपिटल फोरमेशन)

का सवाल बहुत मात्रा में हल हो सकता था । किन्तु इस तरह का आह्वान करने की हिम्मत नेताओं में नहीं थी । और नेताओं में इसका कारण है कि जो एम.पी., और एम.एल.ए., अपनी ही तन्ख्वाह, अपने ही हाथ से बढ़ा लेते हैं, तो उनको यह कहने का साहस कैसे होगा कि लोगों को त्याग करना चाहिए । तो लोगों में त्याग नहीं है यह कहना गलत बात है ।

टैक्नोलॉजी का प्रश्न :

अब टेक्नोलॉजी की बात लीजिए, क्या मॉर्डन टेक्नोलोजी के बारे में सरकार को जानकारी है? वास्तव में विदेश में भी चर्चा चल रही है कि सभी प्रकार के "सांईंटिफिक एड्वान्समेन्ट” यह हितकारक है या नहीं है । हिरोशिमा, नागासाकी ये उदाहरण जब उन्होंने देख लिए, तभी से उनके मन में आया कि '' सांईटिफिक एड्वान्समेन्ट, टेक्नोलोजिकल एड्वान्समेन्ट' ' ज्यादा होगी तो उसके ऊपर कुछ नियंत्रण होना चाहिए, नहीं तो अणु युद्ध हो सकता है, न्यूक्लियर वार हो सकती है और हिरोशिमा, नागासाकी की आवृत्तियां हो सकती है, नियंत्रण होना चाहिए, और इसीलिए वहाँ भी ऐसे शास्त्रज्ञ निर्माण हुए जिन्होंने कहा कि ' 'देयर शुड बी टेक्नोलोजिकल ओमबड्समैन । "टेक्नोलोजी पर नियंत्रण रखने वाला कोई न कोई एक संस्था वहाँ होनी चाहिए, ओमबड्समैन यानि नियंत्रण करने वाली संस्था होनी चाहिए । और उस निकाय में सांईटिस्ट को मत रखिए, टैक्नोलोजिस्ट को मत रखिए, तो जिनको सम्पूर्ण मानवता के बारे में प्रेम है, ऐसे लोगो को उसमें रखिए और उनके नियत्रंण में सांईस और टेक्नोलोजी की प्रगति होनी चाहिए, ऐसा विचार अमेरिका में, यूरोप में भी अभी आया है ।

और दूसरी बात आज भी जो राष्ट्र अध्यक्ष होने वाले हैं, डॉ. अब्दुल कलाम उन्होंने एक किताब लिखी है "इण्डिया 2020” । उस किताब में उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि विदेश से कोई भी टेक्नोलोजिकल सहायता न लेते हुए हमारे लिए आवश्यक जो टेक्नोलोजी है, हमारे टेक्नोलोजिस्ट स्वयं वो विकसित कर सकते हैं । कोई बाहर से टेक्नोलोजिकल एड (सहायता) लेने की आवश्यकता नहीं है और हमारे टेक्नोलोजिस्ट, हमारे साइंटिस्ट अपने भरोसे 2020वाँ साल जब आएगा उसके

पहले ही, भारत को दुनिया के अग्रिम पंक्ति के देशों (फ्रंट रैकिंग नेशन्स) में बिठा सकते हैं । एक ही बात उन्होंने कही कि इसके लिए शर्त एक ही है, कि विल पॉवर चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए। अभाव तो इसी बात का है ।

तो इस तरह से इन्वेस्टमेन्ट के बारे में, टेक्नोलोजी के बारे में उन्होंने अपने हित को ध्यान में रखकर प्रोपेगण्डा किया । हमारे इंग्लिश एज्यूकेटिड लोग, हमारे राजनैतिक नेता उसी के शिकार बन गए, और कहने लगे कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, आत्मनिर्भर नहीं हो सकते । वास्तव में ऐसी बात नहीं है, लेकिन लोगों में देश भक्ति का जागरण होना चाहिए । देश के लिए त्याग करने का आह्वान होना चाहिए, सब कुछ हो सकता है। यह न सोचते हुए, जिस समय विश्व व्यापार संगठन का निर्माण हुआ (वर्ल्ड ट्रेड ऑरगेनाईजेशन) भारत सरकार ने जनता को अंधेरे में रखकर संसद की अनुमति न लेते हुए, संसद को भी अन्धेरे में रखकर सीधे "वर्ल्ड ट्रेड ऑरगेनाईजेशन” की सदस्यता ग्रहण कर ली । खैर! जब वर्ल्ड ट्रेड ऑरगेनाईजेशन के हम सदस्य हो गए उसी समय स्वदेशी जागरण मंच ने कहा, कि यह बहुत गलत बात हुई है इससे देश का नुकसान होगा ।

डब्लू.टी.ओ. का सच - लिट्स और एलबुग की जबानी :

यह विश्व व्यापार संगठन, ये क्या बला है जरा देख लीजिए । जैसा मैंने कहा, कि दूसरा मार्ग समाप्त होने के बाद तुरन्त ही पश्चिमी देशों ने, गोरे देशों ने यह विचार शुरु किया कि नवस्वतन्त्र देशों पर अपना आर्थिक साम्राज्य कैसे फैलाया जा सकता है । कोई नवस्वतन्त्र देश अपने को गुलाम बनाने के लिए तैयार नहीं होगा । उनको गुलाम बनाने की वृति में कैसा लाना चाहिए इसीलिए उन्होंने प्रचार, प्रोपेगण्डा शुरू किया यह मैने प्रारम्भ में कहा । वास्तव में थोड़े विकसित देश, सारे दुनिया के अविकसित और विकसनशील, गैर -गोरे देशों पर, अपना साम्राज्य कैसे स्थापन कर सकते हैं, इसका षडयन्त्र कई दशको से कर रहे हैं, उसी का एक आविष्कार विश्व व्यापार संगठन है । विकसित देशों का साम्राज्य अविकसित देशों पर कैसे हो सकता है विश्व बैंक उसी के लिए, इंटरनेशनल मोनिट्री फण्ड उसी के लिए है, अमेरिकन सरकार भी उसी प्रयास में है।

आपको आश्चर्य होगा, विश्व बैंक के इकोनोमिक एडवाईसर मिस्टर स्टिग लिट्स जिन्होंने अभी तीन साल पहले इस्तीफा दिया है, उनका मूल स्टेटमेंट आप पढ़िए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि विश्व बैंक के "मेमोरण्डम ऑफ एसोसिएशन' ' में जो लिखा था उसके कारण मैंने वहां सर्विस ली, मुझे लगा अच्छे- अच्छे उद्देश्य है। प्रत्यक्ष अब मैंने अनुभव किया कि यहाँ तो गरीब देशों का शोषण करने की प्रक्रिया चल रही है, इसीलिए मैंने उसको छोड़ा है और विश्व बैंक गरीब देशों का शोषण किस ढंग से करती है इसमें प्रक्रिया दी है, चार चरणों में प्रक्रिया दी है : निजीकरण (प्राइवेटाइजेशन) से शुरूआत करके गरीब देश को लोन देना, लोन देते समय अपनी शर्ते लगाना, शर्तों के कारण उसको गरीब बनाना और गरीब बनाने के बाद उसको गुलाम बनाना- यह सारी प्रक्रिया मिस्टर स्टिग लिट्स ने दी है, जिन्होंने अनुभव के आधार पर लिखा है। वैसे ही "इन्टरनेशनल मोनिट्री फण्ड" के टॉप ऑफीशियल डेविसन एलबुग ने तो यहाँ तक लिखा कि "मैंने इतना पाप कर्म किया है इन्टरनेशनल मोनिट्री फण्ड में रहते हुए, कि गरीब लोगों के खून मेरे हाथ पर हैं। और दुनिया की सारी नदियाँ आकर भी मेरा हाथ साफ नहीं कर सकती। इतना खून मेरे हाथ पर है। ", वे यह सब बातें कहते हैं। विश्व व्यापार संगठन इसीलिए स्थापित किया गया कि उसके अन्दर सब देश आ जाए, सब देश आते हैं तो उसमें जो गोरे देश हैं, वह गैर-गोरे देशों पर अपना प्रभाव जमा सके।

वहाँ डब्ल्यू.टी.ओ. की कार्यशैली क्या है? ऐसा है, कि वहां जितने सदस्य हैं, विकसित, अविकसित, गोरे, गैर-गोरे सबने मिलकर और विचार-विमर्श करते हुए निर्णय लेना, यह वास्तव में लोकतान्त्रिक पद्धति है। पर वहाँ वास्तव में ऐसा नहीं होता है। वहाँ क्या करते है कि गोरे देशों के 8-10 प्रतिनिधि पहले इकट्ठा आते हैं, उसको "ग्रीन रूम" कहते हैं और गोरे देशों के हित के लिए गैर गोरे देशों पर क्या निर्बन्ध लगाने चाहिए इसका विचार करते हैं। और वो विचार होने के बाद ग्रीन रूम के बाहर आते हैं और बाहर जो लोग हैं, उनको बताते हैं कि भई यह निर्णय हो चुका है, इसमें चर्चा नहीं, कुछ नहीं।

मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर महाथिर मोहम्मद ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, भारत ने आवाज नहीं उठाई। भारत के प्रतिनिधि जो डब्ल्यू. टी. ओ. में जाते थे वो तो यूरोप, अमेरिका के लोगों के सामने झुक जाते थे। इसीलिए चित्रा सुब्रहमणियम ने एक पुस्तिका लिखी है कि "इण्डिया इज फोर सेल", उसमें दिया है कि कैसे हमारे प्रतिनिधि तैयारी भी नहीं करते, बोलते भी नहीं।

वित्तमंत्रीगण - सत्ता में आने से पहले और बाद में :

बाद में इस परिस्थिति में अन्तर आया, हम लोगों के कारण। तो वहाँ जो गैर - गोरे देश हैं, उनकी ओर से महाथिर मोहम्मद ने सबसे पहले अपनी आवाज उठाई, उन्होंने एक समिति का निर्माण किया, उसका नाम था "साऊथ कमिशन"। उसके अध्यक्ष थे, तंजानिया के मिस्टर न्येरेरे, और जनरल सेक्रेटरी थे डॉ. मनमोहन सिंह और उनको बताया गया कि किस तरह से आर्थिक आक्रमण हो रहा है, किस तरह से आर्थिक साम्राज्यवाद आ रहा है, इसका अध्ययन करना और उसको रोकने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, यह सुझाव देना है। यह काम उसको दिया था, उस कमेटी की रिपोर्ट आपको मार्केट में भी मिल सकती है। "चैलेंजेस टू दी साउथ" उस रिपोर्ट का नाम है। यह पूरी रिपोर्ट डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में बनाई गई है, जिसमें गोरे देशों को कैसे रोका जा सकता है यह भी बताया गया है। साउथ-साउथ कॉ-ओपरेशन जैसे कुछ इलाज बताए गए है कि कैसे आर्थिक साम्राज्यवाद रोक सकते हैं, आप वो पढेंगे तो आपको लगेगा, स्वदेशी जागरण मंच का आदमी है वह लिख रहा है। किन्तु ये ही डॉ. मनमोहन सिंह जैसे ही वित्त मंत्री बन गए जो उन्होंने लिखी हुई बातें थी वो भूल गए, यह आश्चर्य की बात है। जैसे यशवंत सिन्हा की बात है।

स्वदेशी जागरण मंच की एक चिन्तन बैठक नागपुर में हुई थी उसमें तीनों दिन यशवंत सिन्हा उपस्थित थे। आखिरी दिन समारोप में उनका भाषण हुआ। उन्होंने कहा विश्व व्यापार संगठन में रहने के कारण भारत का नुकसान हो रहा है, हमें हिम्मत के साथ विश्व व्यापार संगठन को छोड़ देना चाहिए। यह यशवंत सिन्हा का भाषण था। लेकिन जैसे वित्त मंत्री बन गए अपनी कही हुई बात भूल

गए, मालूम होता है कि फाईनेन्स मिनिस्टर बनते ही एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम अंग्रेजी में है एमनेशिया । एमनेशिया का मतलब है कि पूर्ण विस्मरण, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, सारा भूल जाते हैं । यह एमनेशिया फाईनेन्स मिनिस्टर बनने के कारण हो जाता है इसके द्वारा जैसे डॉ. मनमोहन सिंह वैसे यशवंत सिन्हा भी सब भूल गए और गलत बातें बोलने लगे।

डब्लू. टी. ओ. - मोड़ो या तोड़ो

विकसित देशों के अलग मानदण्ड :

स्वदेशी जागरण मंच चाहता है कि हमारा देश आत्मनिर्भर हो लेकिन विदेशियों का षडयन्त्र चल रहा है कि हमारे देश के कृषि पर, हमारे देश के एक-एक उद्योगों पर विदेशियों का कब्जा हो जाए । अब हमारा कृषि प्रधान देश है । विश्व व्यापार संगठन में सबके लिए एक स्टेण्डर्ड नहीं है । हमारे लिए अलग है । अमेरिका में अपने किसानों को जो पहले सब्सिडी मिलती थी उससे चार गुना सब्सिडी उन्होंने बढ़ाई है । भारत और विकासशील देशों को अमेरिका कहता है तुम अपने सब्सिडी कम करो और आखिर में सब समाप्त करो । अपने किसानों को वे सब्सिडी बढ़ा रहे हैं हमने लोगों को कहा कि सब्सिडी खत्म करो? कारण क्या है? अब देखिए अमेरिका का एक कानून है । 1988 का एक कानून है, उसमें स्पेशल 301 करके क्लॉज है उसमें स्पष्ट दिया है कि "बाहर के देश का यदि कोई भी माल हमारे अमेरिकी बन्दरगाह में आता है और वो हमारे देश अमरिका में उतारने से हमारे देश के उद्योग और कृषि को नुकसान होगा, ऐसा यदि हमें लगता है तो हम बन्दरगाह से माल को उतरने नहीं देंगे, वापिस भेज देंगे ।" लेकिन साथ ही साथ उसमें ऐसा है कि "हमारा (अमेरिका का) माल यदि किसी के यहाँ जाता है उसके बन्दरगाह में हमारा माल उतार लेना ही चाहिए, यदि वे हमारा माल नहीं उतार लेंगे, और अपने मार्केट में नहीं भेजेंगे तो हम उसके ऊपर आर्थिक प्रतिबन्ध लगायेंगे ।" ये कौन सी नीति है?

हमारी सरकार कहती है कि हम "वर्ल्ड ट्रेड ऑरगेनाईजेशन” से कैसे बाहर आ जायेंगे, ये सारा ऑरगेनाईजेशन दुनिया का नहीं है यह विकसित देशों के लिए है, और विकसित देशों के हित के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है । अब देखिए कि वर्ल्ड ट्रेड ऑरगेनाइजेशन में जो विकासशील देशों की मेजोरिटी नहीं उनकी बात मानी नहीं जाती । गोरे देश विकसित देश 8-10 है, सच में तो 8 ही हैं, उनकी दादागीरी सब पर चलती है ।

डब्ल्यु. टी. ओ. की सदस्यता के बाद उपाय :

महाथिर मोहम्मद ने एक बात कही थी । पहले तो महाथिर मोहम्मद ने भारत सरकार को प्रार्थना की कि जितने विकसनशील देश है, उनका एक ब्लॉक बनाने की आवश्यकता है, और चूंकि भारत यह विकसनशील देशों में सबसे बड़ा है, अत: भारत को हमारा नेतृत्व करना चाहिए । हम आपका नेतृत्व मानने के लिए तैयार हैं, यह बात महाथिर मोहम्मद ने सब की ओर से कही । भारत ने नेतृत्व लेने से इंकार कर दिया । फिर उन्होंने यह कहा वर्ल्ड ट्रेड ऑरगेनाइजेशन के अन्तर्गत रहते हुए जो विकसनशील देश है उन्होंने अपना एक ब्लॉक बनाना चाहिए, अपना एक ग्रुप बनाना चाहिए । इस ब्लॉक को विकसित देशों को धमकी देनी चाहिए कि डब्ल्यु. टी. ओ. में आप हमारे साथ इक्वल फुटिंग माने बराबरी का व्यवहार कीजिए । और यदि आप इक्वल फुटिंग का व्यवहार नहीं करते हम डब्ल्यू. टी. ओ. छोड़ देंगे, वो तो इक्वल फुटिंग का व्यवहार करने वाले नहीं है, उनको दादागीरी चलाना है तो डब्ल्यु. टी. ओ. छोड़ देना है और उसके बाद स्वदेशी जागरण मंच ने यह कहा कि विकसनशील देशों ने एक ग्रुप बनाकर पहले डब्ल्यु. टी. ओ. में रहकर धमकी देना और वो मानेंगे नहीं तो डब्ल्यु. टी. ओ. के बाहर आकर दूसरा डब्ल्यु. टी. ओ. दूसरा विश्व व्यापार संगठन विकसनशील देशों को अलग खड़ा करना । सभी विकसनशील देश एकत्रित हो और उन गोरे देशों के साथ हम स्पर्धा करें उनके साथ हम झगड़ा करें ऐसा हम लोगों ने कहा ।

ऐसा है शुरू-शुरू में जब हम बोलते थे, तो वो कहते थे कि आपका बोलने का कोई उपयोग नहीं है । जैसा कहा जाता है कि बुढ़िया कहती तो सच है लेकिन

सुनता कौन है । आपने देखा होगा, ऐसा था कि हम लोग अभी जो नई सरकार आई है, नई सरकार के लोगों से प्रधानमंत्री को लेकर सबके साथ हम बात करते थे उनको समझाने की कोशिश करते थे, उनको समझाते थे तो वे लोग कहते थे कि हम लोग समझ गए हैं, लेकिन हमारे वापिस आने के बाद ब्यूरोक्रेट्स उनके पास पहुंचते थे, ब्यूरोक्रेट्स उनको कहते थे कि अरे यह स्वदेशी वाले यह क्या जानते हैं? मजदूर संघ, किसान संघ वाले अर्थशास्त्र क्या जानते हैं? इनको तो अर्थशास्त्र का पता ही नहीं है, ये केवल भावना प्रधान है, इमोशनल हैं, सेन्टीमेन्टल है तो फिर सरकार का निर्णय बदल जाता था । अब आप जानते है कि शुरू से हमारे देश में एक बीमारी है, अच्छे अच्छे लोग भी खरीदे जाते हैं, लीडर लोग भी खरीदे जाते हैं, कुछ मिनिस्टर भी खरीदे जाते हैं और जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनको खरीदने का प्रतिष्ठित रास्ता भी है, क्रूड मेथड नहीं है । प्रतिष्ठित रास्ता है उनके किसी रिश्तेदार को अमेरिका में सारे शिक्षा-दीक्षा के लिए भेजना, विश्व बैंक में नौकरी देना, आइ. एम. एफ. में नौकरी देना, तरह-तरह के मार्ग हैं जो प्रतिष्ठित दिखते हैं, और इसके कारण हम लोग जो बोलते थे उसका प्रभाव नहीं होता था ।

सरकारें जन दबाव से मानर्ती है. तर्क से नहीं :

हम लोगों ने, मजदूर संघ, किसान संघ ने, बाकी लोगों ने भी अवश्य इसके बारे में आवाज उठाई । वह आवाज जब प्रबल हो गई तो फिर सरकार को भी सोचना पड़ा, कि ब्यूरोक्रेटस की बात मानने से नहीं चलेगा । जनमत जागरण हुआ है और उसके कारण आपने देखा होगा कि दोहा में मिनिस्टर मारन ने वही बात कही जो हम लोग कहते थे । दोहा में मिनिस्टर मारन को कितनी मात्रा में यश आया कितनी मात्रा में अपयश आया यह महत्व का प्रश्न नहीं है । महत्व का प्रश्न यह है कि जहाँ शुरू से लेकर आज तक कभी भी भारत सरकार ने वहाँ प्रतिकार नहीं किया था, वहीं दोहा में प्रतिकार किया और यह हम सब लोगों के दबाव का प्रभाव है यह बात आप ध्यान रखिए । वहाँ से जब मारन वापिस आए तो हमको किसी ने कहा कि आप जाकर अभिनन्दन कीजिए । मारन ने दोहा में जो भूमिका

निभाई उसका हमने सार्वजनिक रूप से अभिनन्दन किया । फिर हमने कहा कि भई जाकर नहीं मिलेंगे । बोले क्यों?

उसी समय से अमेरिका के प्रयास चल रहे थे कि इनके विरोध को कमजोर कैसे बनाया जाए, वहाँ जो विश्व व्यापार संगठन में कमजोर देश है, बिल्कुल गरीब देश है, उनको खरीदने का काम वही शुरू हुआ था । उनको खरीदने का काम, उनके प्रतिनिधियों को कहना कि तुम चले जाओ । और वहीं से ये काम शुरू हुआ था । हमारे कुछ ब्यूरोक्रेटस तो पहले से खरीदे गए हैं, बाकी लोगों को भी कैसे खरीदा जा सकता है, यह अमेरिका का प्रयास चल रहा है, हम जानते हैं । इसीलिए हमने कहा कि हम मिनिस्टर मारन को धन्यवाद देते हैं और अभिनन्दन करते हैं, किन्तु प्रत्यक्ष जाकर हम नहीं मिल सकते क्योंकि दो साल के अन्तर्गत क्या-क्या परिणाम होंगे यह देखना बाकी है । मंत्री परिषद् में भारत सरकार अपनी भूमिका दोहा के जैसे नहीं रखे इसके लिए अमेरिका जी -जान से कोशिश कर रहा है, क्या उस कोशिश का प्रभाव होता है या हम लोगों का प्रभाव जैसा था वैसे कायम रहता है, यह देखना पड़ेगा । क्योंकि सरकार आरग्युमेन्टस नहीं सुनती, यह दुख की बात है । आरग्युमेन्टस से वह नहीं मानती, दबाव से मानती है । पहले विश्व बैंक, इंटरनेशनल मोनिट्री फण्ड, अमेरिकन सरकार, यूरोप की सरकारें, इनका दबाव था इसके कारण सरकार में लोग स्वदेशी विरोधी नीति लेकर चले थे । बीच में स्वदेशी जागरण मंच, मजदूर संघ, किसान संघ और बाकी सभी लोग हैं, सभी लोगों ने आवाज उठाई, उस दबाव में आकर दोहा में ठीक भूमिका भारत सरकार ने ली । किन्तु अभी अगले मंत्री स्तरीय वार्ता में फिर से दोहा की भूमिका नहीं अपना ले, सरकार ने झुकना चाहिए, यह प्रयास चल रहा है । इसके कारण डब्ल्यु. टी. ओ. के अगले मंत्री परिषद् तक में अभी थोड़ा समय रहा है । सवा साल का समय रहा तो हमें इतना जन-जागरण करना है, इसके कारण हमारा दबाव फिर से आ जाए, जनमत का दबाव फिर से आ जाए और अमेरिकन दबाव के सामने जो सरकार झुकती है, उनको पता चले कि यदि हम अमेरिकन सरकार के समक्ष झुकेंगे तो फिर हमारी भी जान खतरे में है । इसीलिए हमारे दबाव के

कारण वो ठीक भूमिका जैसे दोहा में ली वैसी उन्होंने लेनी चाहिए। इतना जन - जागरण और जनमत का प्रभाव बढ़ाना चाहिए ।

मतदाता भारतीय हैं, विदेशी नहीं :

हमने हमारी सरकार से यह कहा भारतीय मजदूर संघ का अखिल भारतीय अधिवेशन त्रिवेन्द्रम में हुआ था । वहाँ ओपन-सैशन हुआ, बहुत बड़ी अच्छी हाजरी थी उसने सारी यह स्वदेशी वगैरह की बात हमने कही । और उसके बाद हमने यह कहा कि भई भाजपा की सरकार को हमारे हित के लिए छोड़िए- किसान मजदूरों के लिए छोड़िए, अपने खुद के लिए तो कुछ अपना काम करना चाहिए, भाजपा की इज्जत बचाने के लिए तो उन्होंने काम करना चाहिए । मैंने यह कहा कि आप गलत नीतियां अपना रहे हैं, आर्थिक नीतियां गलत अपना रहे हैं, जिसके कारण लाखों मजदूर बेरोजगार होने वाले हैं, किसान भूखे मरने वाले हैं । आत्महत्या, किसान पहले ही कर रहे हैं, पहले ही वह कर्जे में हैं, कैसे कर्जा भरना नहीं जानते । आप बाहर से माल ला रहे हैं, आयात शुल्क उठा लिया मात्रात्मक प्रतिबंध (क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिशन) उठा लिया इसके कारण कृषि का माल जो विदेश से आता है, वो सस्ते में बेचा जाता है । हमारे कृषकों का माल ज्यादा महंगा हो जाता है इसीलिए वह पड़ा रहता है कृषकों को आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा । लाखों मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं ।

तो त्रिवेन्द्रम में हमने कहा कि- भई आप अपनी पार्टी का तो विचार कीजिए, आपके पार्टी को आज नहीं कल, कल नहीं परसों चुनाव में आना पड़ेगा या नहीं? तो चुनाव में आपके जो मतदाता रहेंगे, वो अमेरिकन नहीं रहेंगे जिनके दबाव में आप हर काम कर रहे हैं, वह यूरोपियन नहीं रहेंगे जिनके दबाव में आकर आप काम कर रहे हैं; वह तो भारतीय रहेंगे और भारतीय लोगों को आप यदि गलत ढंग से और उनको सतायेंगे आपको मत कैसे मिलेंगे? संयोग की बात थी कि त्रिवेन्द्रम में हमारा भाषण हुआ । दूसरे दिन से इलेक्शन के रिजल्ट्स आना शुरू हुआ उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तरांचल और सारे रिजल्ट्स आए, आप जानते हैं । कोरेसपोन्डेन्ट्स हमारे पास आए क्या ठेंगडी जी आप जानते थे कि क्या-क्या

होगा? हमने कहा हम जानते नहीं थे । यह कॉमन सेन्स की बात है । तो अपने पार्टी के हित के लिए तो भी, इन्होंने बहुत ठीक ढंग से व्यवहार करना चाहिए ।

प्रिंट मीडिया में विदेशी निवेश :

ठीक ढंग से व्यवहार नहीं हो रहा इसका एक ही उदाहरण देकर और मैं यह भाषण पूरा करना चाहता हूँ । अभी- अभी की बात है, फोरेन प्रिंट मीडिया की । फोरेन इन्वेस्टमेन्ट प्रिंट मीडिया में लाना है यह पुराना षडयन्त्र है । पुराना षडयन्त्र है, नई बात नहीं है । चुनाव होने के पहले हमने बीजेपी के नेताओं को कहा था, कि आप इनफोरमेशन टैक्नोलॉजी डिपार्टमेन्ट फलाने- फलाने आदमी को मत दीजिये । उन्होंने कहा अरे आश्चर्य की बात है अभी तो चुनाव हुआ ही नहीं, आप पर्टीकुलर आदमी का नाम ले रहे हैं, पर्टीकुलर डिपार्टमेन्ट का नाम ले रहे हैं, तो हमने कहा कि हम अफवाहों के आधार पर ऐसा नहीं कह रहे । मेरे पास डायरेक्ट जानकारी है कि इस आदमी को अपना हथियार बनाकर, अपना माध्यम बनाकर हिन्दुस्तान के मीडिया पर छाने का षडयन्त्र विदेशियों का है ।

उसको इतने दिन हो गए, इन्होंने प्रयास किया । प्रिंट मीडिया में विदेशी निवेश का प्रेस वालों ने विरोध किया । जॉइन्ट पार्लियामेन्ट्री कमेटी इसके लिए बिठाई गई, उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारे प्रिंट मीडिया में फारेन इन्वेस्टमेन्ट नहीं आनी चाहिए । अचानक निर्णय आया कि प्रिंट मीडिया में फारेन इन्वेस्टमेन्ट आ रही है । अब निर्णय लिया, प्रेस वालों के विरोध के बावजूद, जॉइन्ट पार्लियामेन्ट्री कमेटी के विरोध के बावजूद जनता की राय न लेते हुए, पार्लियामेन्ट की राय ने लेते हुए, एकदम यह अचानक हमला आ ।

सर्वसहमति का दुष्प्रचार :

लेकिन अपनी चमड़ी बचाने के लिए एक प्रचार शुरू किया, क्या था, उनमें कहा कि प्रिंट मीडिया में फारेन इन्वेस्टमेन्ट आनी चाहिए, इस बात को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर-संघचालक माननीय सुदर्शन जी भी अनुमति दे रहे हैं, उनकी भी इच्छा है, अब इतनी झूठी बात आकाशवाणी से बार-बार प्रसारित होती है आपने सुना होगा, और समाचार पत्रों में से, कई समाचार पत्र । मैं ऐसा नहीं

कहता, सभी समाचार पत्र झूठ लिखते थे । "ए सेक्शन ऑफ द प्रेस”, कई समाचार पत्र इसका प्रचार कर रहे थे । वास्तव में सुदर्शन जी ने यह कहा ही नहीं, सुदर्शन जी को जब पूछा गया तो सुदर्शन जी ने कहा कि फारेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेन्ट को हम लाए इसका उन्होंने स्वागत नहीं किया । उन्होंने कहा कि फारेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेन्ट को तो मत लाईए, लेकिन हाँ एन. आर. आई. है, एन. आर. आई माने अनिवासी भारतीय, उनका पैसा यदि आता है, उसमें आपत्ति नहीं है, तो उन्होंने एन. आर, आई. का स्वागत किया फारेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेन्ट का स्वागत नहीं किया । सरकार ने गलत ढ़ंग से प्रचार किया, अब इससे और गलत काम क्या हो सकता है?

मीडिया में विदेशी निवेश-स्वदेशी मंच का दृष्टिकोण :

वास्तव में स्वदेशी जागरण मंच प्रिंट मीडिया में जो फारेन इन्वेस्टमेन्ट आ रही है उसका विरोध कर रही है । इतना ही नहीं इलेक्ट्रोनिक मीडिया में फारेन इन्वेस्टमेन्ट है, हमारा कहना है कि इलेक्ट्रोनिक मीडिया से पूरी तरह से जो फारेन पैसा जो है, वापिस जाना चाहिए । तो हम तो इलेक्ट्रोनिक मीडिया में से भी फारेन इन्वेस्टमेन्ट वापिस हो जाए ऐसा कह रहे हैं । और वे कह रहे हैं कि फारेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेन्ट का आर.एस.एस. ने स्वागत किया, इससे और झूठ बात क्या हो सकती है, मानो वह अभी झूठ बोलने पर भी, प्रेस के कुछ लोग, सरकार के कुछ लोग उतारू हो गए हैं ऐसा दिखते हैं, ऐसी परिस्थिति में से हम जा रहे हैं ।

विनिवेश भी गलत तरीके से :

सवा साल के बाद डब्ल्यु. टी. ओ. का मंत्री परिषद का जो मामला आने वाला है उसके लिए दबाव बनाना है और यह जो एक-एक उद्योग विदेशियों के हाथ में जा रहा है, प्राईवेटाईजेशन कहते हैं, अरे जो प्रोफिट मेकिंग इण्डस्ट्रीज है, वो भी आज प्राईवेट लोगों को दिया जा रहा है । अगर आपको देना ही है तो वहाँ के मजदूरों को दीजिए, अपने- अपने उद्योग वहाँ के मजदूर चला सकते हैं । लोग कहते हैं मजदूर कैसे चलायेंगे? हमने कहा मिनिस्टर को भी क्या जानकारी होती है, वो भी मैनेजर और टैक्नोलोजिकल लोगों की सहायता से चलाते हैं, मजदूर भी

चलायेंगे । लेकिन पब्लिक सेक्टर की प्रोफिट मेकिंग इण्डस्ट्रीज का भी प्राईवेटाईजेशन कर रहे हैं ।

आह्वान

एक-एक बात गलत ढ़ंग से चल रही है । इस दृष्टि से जन-जागरण हो, लोगों को शहरों में, गांवों में, इस बात का पता चले कि गलत नीतियाँ है, और उसके कारण एक प्रचण्ड दबाव, इधर से दबाव आएगा । विश्व बैंक, इंटरनेशनल मोनिट्रि फण्ड, अमेरिकन सरकार, यूरोप की सरकारें इनका दबाव आएगा, और उनका विरोध करना है तो इधर से जबरदस्त दबाव जनमत का जन-जागरण का जाना चाहिए, तभी तो देश को बचाया जा सकता है, वरना अपना देश भी आर्थिक साम्राज्यवाद में आ जाएगा । तो हमारी सोवेरेनिटी खतरे में है, सम्प्रभुता खतरे में है ।

सोवेरेनिटी की परिभाषा अपने शास्त्रों ने की है, **''इक्षवांकुनामियम् भूमि सशैले जनकानना, मृगपक्षमनुष्याणाम् निग्रहानुग्रहेशु"** याने सारी भूमि इक्षवाकु की है, शैल, जल, कानन इनके साथ सभी भूमि इक्षवाकु की है, '**मृगपक्षमनुष्याणाम्**' मृग हो पक्षी हो, मनुष्य हो सबका निग्रहानुग्रहेशु अपि अपना निग्रह करना और उन पर अनुग्रह करना, इसका पूरा अधिकार इक्षवाकु को है । यह सारी सोवेरेनिटी की परिभाषा है । हम सोवेरन है ऐसा लिखा गया है । लेकिन सोवेरेनिटी पर आच आ रही है, आक्रमण हो रहे है । अपनी सोवेरेनिटी जाएगा, इन्डिपेन्डेन्स जाएगा । इस दृष्टि से यह जो गोरे देशों का षडयन्त्र है, उसको फेल करने के लिए, और उस दृष्टि से भारत सरकार स्वदेशी के पक्ष में रहे, विदेशियों के पक्ष में न रहे यह दबाव सरकार पर लाने के लिए सब लोगों ने ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना चाहिए, इतनी ही प्रार्थना करते हुए मैं मेरा भाषण पूरा करूंगा ।

गोरे देशों की दादागिरि नही चलेगी

(13 सितम्बर, 1998 आबू रोड़)

मान्यवर उपस्थित देश प्रेमी प्रबुद्ध बन्धु नागरिक एवं भगिनिगण । वैसे तो दुनिया में हमेशा परिवर्तन चलता रहता है । विविध देशों में विविध उथल-पुथल चलती रहती है, किन्तु विश्व के इतिहास को मोड़ देने वाली घटनाएं बहुत कम रहती हैं । ऐसे चलता ही रहता है, युद्ध चलता रहता है, क्रांति चलती रहती है, सत्तांतरण चलता रहता है । किन्तु विश्व के इतिहास को मोड़ देने वाली घटनाएँ कभी-कभी होती है ।

विश्व को प्रभावित करने वाली दो घटनाएँ

पिछले साठ साल में, ऐसी दो घटनाएँ हुई हैं । 6 जून 1945 को जनरल आइसन हावर ने मित्र राष्ट्रों की सेना को यूरोप के कॉन्टीनेन्ट पर फ्राँस में उतारा । वह एक दिन ऐसा था, जो विश्व के इतिहास को मोड़ देने वाला था । और दूसरा दिन 13 दिसम्बर 1996 को सिंगापुर में विश्व व्यापार संगठन के अन्तर्राष्ट्रीय अधिवेशन में जो कुछ हुआ वह दिन विश्व के इतिहास को नया मोड़ देने वाला था ।

पहली घटना जब हुई तो दूसरा महायुद्ध समाप्त हुआ । मित्र राष्ट्रों की विजय हुई, किन्तु उनके ध्यान में आया कि अब तक जो उनका साम्राज्य दुनिया भर में चल रहा था, वैसे साम्राज्य चलाना अब सम्भव नहीं है । अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का ऐसा दबाव था, कि अपने उपनिवेशों को स्वराज्य देना उनके लिए बाध्य हो गया था । सभी को स्वराज्य मिला, भारत बड़ा देश है उसको भी मिला, सिंगापुर छोटे से छोटा उसको भी मिला । सभी देशों को स्वतंत्र करना उनके लिए बाध्य था, अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति के दबाव के कारण ।

शोषण की पुरानी पद्धति समाप्त - नयी पद्धति की तैयारी :

किन्तु यह एक बड़ा संकट भी था उनके लिए । पहले दुनिया भर में उनका एक ऐसा रूबाब था कि यह देश बड़े समृद्ध हैं । किन्तु वास्तव में उनकी समृद्धि अपने पैरों में नहीं थी, उपनिवेश का शोषण करते हुए वह समृद्ध थे । अब उनके सामने एकदम प्रश्न आया, कि अपने उपनिवेशों को हम यदि स्वराज्य देते हैं, स्वराज्य देने के बाद शोषण कैसे करेंगे, और शोषण यदि बन्द हो जाता है तो फिर हमारी अर्थव्यवस्था चरमराने लगेगी ।

माने परिस्थिति ऐसी थी, कि उनकी ही अर्थव्यवस्था चरमराने लगती यदि दूसरे देशों का शोषण बन्द हो जाता । लेकिन ऐसे शोषण कौन करने देगा? जो नवस्वतंत्र देश है, वहां के स्वाभिमानी लोग यह पसन्द नहीं करेंगे, कि स्वराज्य प्राप्ति के बाद भी और कोई उनके देश का शोषण करे । उनके जो एक्सपर्ट थे, उन्होंने तभी से योजना बनाना शुरू किया, रणनीति (स्ट्रेटेजी) बनाना शुरू किया । यह सोच लिया कि बगैर शोषण के हम जिन्दा नहीं रह सकते? किन्तु शोषण होने देने के लिए कौन तैयार होगा?

अब एक टरमिनोलोजी आप ध्यान में रखिए, नवस्वतंत्र देश, तृतीय विश्व के देश, विकसनशील देश और दक्षिण देश ये सब एक ही देश, वही देश हैं उनके लिए चार्ज सौंप के आए सन्दर्भ के अनुसार आती है, कभी नवस्वतंत्र देश, कभी विकसनशील देश, कभी तृतीय विश्व के देश कभी दक्षिणी देश ।

अब यह जो पूर्व साम्राज्यवादी गोरे देश थे, दुनिया का नक्शा, एटलस ऐसा है कि सारे पूर्व साम्राज्यवादी गोरे देश उत्तर में आते हैं, और सारे गोरे देश जो विकसनशील, दक्षिणी, नवस्वतंत्र, तृतीय विश्व के वो सारे दक्षिण में आते हैं। इसीलिए यह भी टरमीनोलोजी चलती है कि दक्षिणी देश माने पुराने उपनिवेश, उत्तरी देश माने पूर्व साम्राज्यवादी गोरे देश, और उनका नेतृत्व उस समय अमेरिका की तरफ था, दूसरे महायुद्ध के पश्चात् अमेरिका एकदम दुनिया का नेता माना गया, क्योंकि सबसे कम हानि युद्धमान देशों में अमेरिका की हुई थी । बाकी सब देशों की भूमि पर लड़ाई लड़ी गई थी । अमेरिका दूर था इसीलिए अमेरिका

की जमीन पर लड़ाई नहीं लड़ी गई, इसीलिए सबसे कम हानि उनकी हुई थी और फिर उनकी अर्थव्यवस्था सबसे अच्छी थी, उनको दुनिया का नेता माना गया ।

अब दो तरफ दो बातें हुई । एक तरफ तो गोरे देशों ने नव-स्वतन्त्र देशों का शोषण कैसे करना है, इसीलिए रणनीति; यह बनाई कि सभी नवस्वतंत्र देशों में अमेरिका के लिए उपयुक्त, मैं अमेरिका शब्द का प्रयोग कर रहा हूं यह माने सभी गोरे देशों के लिए, उपयुक्त अनुकूल ऐसे लोगों को सरकार में लाना । राज्यकर्त्ता इन देशों के ऐसे ही हो, जो अमेरिका के लिए अनुकूल होंगे और स्वाभाविक रूप से यदि ऐसे लोग नहीं आ सकते तो खून खराबा करते हुए भी अमेरिका के लिए अनुकूल लोगों को लाना । जैसे चिली में अयण्ड का खून किया गया । तो राज्यकर्त्ता अपने अनुकूल रहे यह पहली बात । रणनीति का दूसरा हिस्सा यह था कि इन सभी देशों के लोगों को अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक घटनाओं के बारे में पूरी तरफ अंधेरे में रखना । टी.वी. है, रेडियो है, समाचार पत्र है, बड़ी-बड़ी अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक घटनाएं जो हैं, उनके बारे में अंधेरे में रखना। फिर तीसरा था कि यह जो अपने लिए अनूकूल राज्यकर्ता लाए गए, जनता को पता न लगते हुए, उनके पार्लियामेण्ट को पता न लगते हुए, उनके साथ गोरे देशों के लिए अनुकूल ऐसे समझौते करना । फिर यह समझौते जैसे के जैसे प्रकाशित नहीं करना, उसमें से जो हिस्सा अच्छा होगा, मीठा-मीठा, गप-गप, तो उतना ही प्रकाशित करना । पूरा प्रकाशित नहीं करना, ताकि एकदम विरोध नहीं होता और जब अमल करना शुरू होता है, फिर लोगों को पता चलता है कि यह तो बड़ा घातक समझौता हुआ किन्तु समय पर क्या करना, सब लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं । लगता है कि आकाश से कुल्हाड़ी गिर गई, अब क्या करना, फिर कोई प्रतिकार नहीं कर सकेगा, अपना काम हो जाएगा । यह उनकी रणनीति थी । अब उसके अनुसार वह चले, सभी देशों में चले, अपने देश में भी चले ।

विकसित देशों की स्थिति खतरे में :

अब उधर दूसरी बात थी, अमेरिका दूसरे महायुद्ध के पश्चात् दुनिया का नेता बन गया यहां तक तो ठीक है । (उससे उसमें छाया) 'यूफोरिया', यूफोरिया, माने

हर्षोन्माद कि अब हम ही हैं, हम दुनिया के नेता हैं, जब तक आसमान में चांद, सूरज हैं हम ही दुनिया के नेता रहेंगे । जैसा राज्यकर्त्ता के मन में हमेशा रहता है कि अब हम पॉवर में है, तो जब तक आसमान में चांद सूरज हैं, हम ही पॉवर में रहेंगे, ऐसी भ्रांति अमेरिका के लोगों के मन में थी । तो उन लोगों को लगा कि हम अखण्ड समृद्धिमान रहेंगे, तो वो भौतिकतावादी (मेटीरियलीस्टीक) होने के कारण उपभोगवादी (कंज्यूमरिस्ट) थे । ये कोई ईज्म नहीं है । जबसे धरती पर जीवन निर्माण हुआ तबसे कंज्यूमरिज्म निर्माण हुआ, छोटे से छोटा प्राणी भी कंज्यूमरिज्म ही होता है, ज्यादा गर्म हुआ तो वो ठण्डे प्रदेश में आता है, ज्यादा ठण्डा हुआ तो वो गर्म प्रदेश में जाता है । तो कंज्यूमरिज्म, उपभोगवाद यह सृष्टि के प्रारम्भ से है, तो उपभोगवाद बहुत बढ़ गया, अब कैपिटलिज्म का उपभोगवाद का एक अन्तरविरोध यह है कि दुनिया में उपभोग के साधन सीमित हैं, सभी सम्पूर्ण दुनियां में उपभोग के साधन सीमित हैं, और मनुष्य की उपभोग की इच्छाएं असीम हैं, अमार्यादित है । तो उपभोग की इच्छाएँ अमर्यादित, उपभोग के साधन सीमित । यह अन्तरविरोध कैपिटलिज्म में, कंज्यूमरिज्म में है । अमेरिका में यही हुआ, उपभोग की इच्छाएँ बढ़ती गई । शुरू- शुरू में 10 - 15 साल कुछ लगा नहीं, लेकिन उपभोग के साधन सीमित थे, और फिर दुनिया के नेता के नाते जो उनका स्थान था, वह भी खतरे में आने लगा ।

गेट, डब्ल्यु. टी. ओ. - व्यापारिक आधिपत्य हेतु बढ़ता दायरा :

तो उन्होंने पहले से जो योजनाएं बनाई, उसमें से एक योजना यह थी, कि 1948 ही में उन्होंने एक सस्था बनाई, "जनरल एग्रीमेन्ट ऑन ट्रेड एण्ड टैरिफ", गैट । इसका उद्देश्य क्या बताया, उद्देश्य बताया कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं का व्यापार ठीक चले, सबके लिए अनुकूल चले, व्यवस्थित चले, इसीलिए हम यह संस्था बना रहे है । अब उसमें एक ही एजेण्डा रखा कि वस्तुओं का व्यापार, "इन्टरनेशनल ट्रेड ऑफ गुड्स" गुड्स यानि वस्तु । उस समय सभी वस्तुओं में अमेरिका आगे था । तो इसमें लाभ अमेरिका को होगा, बाद में ऐसा हुआ कि कई चीजों में अमेरिका पिछड़ गया । जापान आदि कुछ देश आगे बढ़ गए, केवल गुड्स यानि वस्तुओं के आधार पर अमेरिका को अपना स्टेटस कायम रखना

कठिन हो गया । तो 1986 में गैट के ऊरूग्वे राऊण्ड (जिसने डब्ल्यु. टी. ओ की नींव डाली) में उन्होंने कहा कि भई और चार आईटम्स गैट के टेबल में आने चाहिए । हमें डीटेल में नहीं जाना चाहिए, ट्रिप्स है, ट्रिम्स, सर्विसेज, एग्रीकल्चर चार आईटम्स उन्होंने गुड्स के साथ और लाने के लिए कहा । तो गैट में जो विकसनशील देश थे, उन्होंने कहा कि अरे भई ये तो ओरीजनल नहीं था । केवल गुड्स के बारे में था, उन्होंने कहा नहीं - नहीं हम किसी की मानेंगे ही नहीं, यह चार आईटम्स आने ही चाहिए । दादागीरी करके उन्होंने वह आईटम्स लाए । बाद में उनके यह खयाल में आया कि इससे भी अमेरिका अपने को बचा नहीं सकता, तो इसीलिए और भी आईट्मस लाने का प्रयास उनका चल रहा है । इसी में से डंकल आपने सुना होगा, फिर बाकी बातें हुई ।

अमर्यादित उपभोगवाद से खतरे में आए गोरे देश :

उधर 1972 तक किसी भी पॉलिटिकल लीडर की अमेरिका में हिम्मत नही थी यह बताने की कि वास्तविकता क्या है? कि भई उपभोगवाद के कारण हमारा देश नीचे जा रहा है, यह सीधा बताना पॉलिटिकल लीडर के लिए कठिन था क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल लीडर कहेगा, कि भई उपभोगवाद कम करो, नहीं तो हमारी अर्थव्यवस्था टूट जाएगी, लोग नाराज हो जाएंगे । इसीलिए किसी ने हिम्मत नहीं की, अपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जैसे फॉर्मूला दिया, अधिकतम उत्पादन, समानतर वितरण, कम से कम उपभोग (मैक्सीमम प्रॉडक्शन, इक्वीटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, रिस्ट्रीक्टेड कन्जम्पशन) । ऐसा कहने की हिम्मत (वहाँ) किसी की नहीं थी ।

अमरीका के दोहरे मानदण्ड :

1972 तक अमेरिका की अर्थव्यवस्था इतनी गिरी कि अब छिपाना कठिन हो गया, तो 1973 में उन्होंने कानून बनाया, अर्थव्यवस्था को थोड़ा संवारने के लिए । लेकिन उसका भी उपयोग नहीं हुआ, तो 1988 में एक नया बड़ा कानून बनाना पड़ा, ऑमनीबस एक्ट बड़आ कानून बनाना पड़ा, अमेरिका की अर्थव्यवस्था को संवारने के लिए जिसमें, वो सुप्रसिद्ध दो क्लाजिस है, सुपर 301, स्पेशल 301

जिसके अन्तर्गत यह कहा गया है कि अपने देश में किसका माल आयात करने देना यह तय करने का अधिकार अमेरिका को रहेगा । किसी भी देश का माल आया, अमेरिका को ऐसा यदि लगा कि यह माल आने के कारण हमारे (अमेरिकन) उद्योगों को हानि पहुंचती है, तो उनको अधिकार है कि वह यह माल उतारने नहीं देंगे । किन्तु अमेरिका का माल किसी भी देश में यदि निर्यात होता है, तो सभी देशों के लिए बाध्य है कि उन्हें अमेरिका का माल उतारना ही चाहिए, लेना ही चाहिए । नहीं लेंगे तो उनको दुश्मन कहा जाएगा । उनके खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाया जाएगा, माने डबल स्टैण्डर्ड, अपने देश में कौन सा माल आने देना यह तय करने का अधिकार अमेरिका को है, यह किसी भी दूसरे देश का यह अधिकार नहीं है । अमेरिकन माल आता है वह लेना ही पड़ेगा, नहीं लेंगे तो हम प्रतिबन्ध लगायेंगे, यह धमकी है । तो यह 1988 का ऑमनीबस कानून उन्होंने पास किया । किन्तु उससे भी पोजीशन सुधरना कठिन था, तो अमेरिका धीरे- धीरे नीचे जा रहा था । अब और भी उन्होंने कुछ तरकीबें लाई, वह सारा गहराई में जाकर बोलना आपके लिए बड़ा बोर हो जाएगा । वास्तव में मैं जो बोल रहा हूँ वह भी इतना टेक्नीकल है, कि बहुत सारे लोगों को नींद आने लगी होगी, किन्तु विषय ही टैस्नीकल है अब कोई चारा नहीं । पॉलीटीकल भाषण लच्छेदार हो सकता है, हम भी कर सकते हैं, किन्तु यह आर्थिक प्रश्नों का भाषण लच्छेदार नहीं हो सकता वो फैक्टस एण्ड फिगर्स वाला ही हो सकता है ।

डब्ल्यु. टी. ओ. - आधिपत्य का साधन

तो फिर इन्होंने अपने साधन के रूप में एक संगठन निर्माण किया जिसका नाम है "विश्व व्यापार संगठन", "वर्ल्ड ट्रेड ऑरगनाईजेशन" । अब यहां एक बात का मैं स्पष्टीकरण करूंगा, मैं जब अमेरिका, अमेरिका कहता हूँ? तो कृपया करके ऐसा मत समझिए कि मैं अमेरिकन जनता के विरोध में बोल रहा हूं । जनता के विरोध में नहीं बोल रहा हूँ, अमेरिका के सर्वसाधारण लोग उतने ही सज्जन और निरीह हैं जितने आप और हम। मैं जब अमेरिका शब्द का प्रयोग करता हूं? उसका अर्थ है, कि सभी गोरे देश पूर्व साम्राज्यवादी सभी गोरे देश जिनको विकसित देश, डवल्पड कन्ट्रीज भी कहा जाता है। ऐसा डवल्पड कंट्रीज के राज्यकर्ता और

डवल्पड कन्ट्रीज के पूंजीपति इनकी जो सांठ-गांठ है । राज्यकर्ता और केपिटलिस्ट इनकी जो सांठगांठ है, उसको हम कन्डेम कर रहे हैं । अमेरिका के या बाकी गोरे देशों के सर्वसाधारण नागरिकों के खिलाफ हम नहीं है, उनको पता ही नहीं, उनका कोई कसूर नहीं नहीं, उनको भी मालूम नहीं कि यह ऊपर के लोग क्या बदमाशी कर रहे हैं, तो जब इतना हर समय बोलना तो कठिन है कि गोरे देशों के राज्यकर्त्ता और कोई पूंजीवादी संस्थाएं इनकी साठगांठ का हम विरोध करते हैं, हर समय बोलना कठिन है इसीलिए सुविधा के लिए हम अमेरिका शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसका अर्थ यह होता है, अमेरिकन जनता से हमारा विरोध नहीं है । तो इन लोगों ने यह विश्व व्यापार संगठन क्यों खड़ा किया? जब मैं विदेशी पूंजी कहता हूं फोरेन केपिटल, तो उसमें आते हैं, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मोनेट्री फण्ड, और बहुराष्ट्रीय कम्पनियां (मल्टीनेशनल) अब ये शुरू में उनकी इच्छा थी कि तृतीय विश्व के देशों पर अपना कब्जा जमाएँ, उनका शोषण करें, तो गैट के नेगोसिएशन टेबल पर सभी विकसनशील देश इनके ऊपर दादागिरी करते हुए गोरे देश अपने निर्णय थोपते थे ।

न्यायपूर्ण व्यवस्था हेतु हुए प्रयास :

तो उस समय मलेशिया के प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद, इन्होंने सोचा कि यह जो दादागिरी कर रहे हैं, इसका विरोध होना चाहिए, विरोध होना चाहिए तो यह जो गैर-गोरे विकसनशील देश है, उनको इकट्ठा लड़ना चाहिए, और यह जो शोषण का प्रयोग चल रहा है उसके बारे में अध्ययन होना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए, तो इन्होंने भारत को कहा कि सबसे बड़े देश हम में से आप ही हैं । तो गैट के नेगोसिएशन में गोरे देशों का हम सब मिलकर विरोध करें आपके नेतृत्व में, भारत के नेतृत्व में । भारत ने नेतृत्व करने से इन्कार किया, फिर महाथिर मोहम्मद ने दूसरी तरकीब निकाली, एक कमीशन स्थापित किया "साऊथ कमीशन” इन देशों के एक्सपर्टस को लेकर एक कमेटी बनाई, व उसको साऊथ कमीशन कहा । उसको काम दिया, क्या काम दिया, कि ये गोरे देशों का आर्थिक आक्रमण कैसे हो रहा है? उनके आर्थिक साम्राज्य कैसा आ रहा है? और उसको रोकने के लिए क्या कारगर उपाय हो सकते हैं? इसके लिए कमीशन बनाया । इस कमीशन की

रिपोर्ट आई व पब्लिश भी हुई, 'चेलेंज टू द साऊथ' यह रिपोर्ट का नाम है । आप कहीं भी मार्केट में ले सकते हैं 'चेलेंज टू द साऊथ' ।

मनमोहनसिंह - नीत रिपोर्ट स्वदेशी की आग्रही :

और उसका रिपोर्ट आप पढ़ेंगे तो स्वदेशी जागरण मंच आज जो बातें बोलता है, वही बातें उसमें है कि यह गोरे देश सबको आर्थिक गुलामी में डालना चाहते हैं, उसका विरोध करना चाहिए, उसके लिए उपाय क्या-क्या हो सकते हैं, साऊथ कॉ- ऑपरेशन माने दक्षिणी देशों ने आपस में कॉ- ऑपरेशन करना वगैरह -वगैरह ऐसा एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ । आप रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आपको लगेगा यह स्वदेशी जागरण मंच के लोगों ने लिखा है । अब यह किसने लिखा था, यह जो साऊथ कमीशन था, उसके अध्यक्ष के नाते महाथिर मोहम्मद तंजानिया के मि. न्येरे को अध्यक्ष रखा था, और जिनके वैचारिक नेतृत्व में यह डॉक्यूमेन्ट तैयार हुआ, वो सेक्रेटरी जनरल डॉ. मनमोहन सिंह थे । आपको आश्चर्य होगा कि सारा जो डॉक्यूमेन्ट स्वदेशी जागरण मंच के विचारों के जैसा है, वो जिनके वैचारिक नेतृत्व में तैयार हुआ वह डॉ. मनमोहन सिंह थे ।

बाद में हो गया विस्मरण :

लेकिन जैसे फाइनेन्स मिनिस्टर के नाते शपथ ली, तो अंग्रेजी में कहते हैं, एमनेशिया करके एक बीमारी होती है, एमनेशिया का मतलब होता है कि आदमी भूल ही जाता है, मैं कौन हूँ क्या हूँ? कहाँ से आया, कहाँ जाना है, मेरा नाम क्या है, सब भूल जाता है, सम्पूर्ण विस्मरण! तो जैसे ही फाइनेन्स मिनीस्टर बन गए, सम्पूर्ण विस्मरण, एमनेशिया हो गया और रिपोर्ट में उन्होंने जो लिखा था, उसके विपरीत बोलना शुरू कर दिया । खैर, अब धीरे- धीरे लोगों में जागरण होना शुरू हुआ ।

विरोध विश्वव्यापी हुआ :

अब उनकी जो है रणनीति, मैंने बताई, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा एक था, कि जो वो करना चाहते थे, वह तुरन्त हो जाए, क्योंकि तुरन्त न हुआ और लोग यदि

सावधान हो गए तो फिर उसको अमल में लाना बड़ा कठिन होता है । इसीलिए जल्दबाजी करने की आवश्यकता थी । किन्तु भगवान की इच्छा थी कि वो वैसा पूरा कर नहीं सके । इधर चाईना ने, पहले चाईना दबता था, धीरे- धीरे अपनी अर्थव्यवस्था अच्छी होने के बाद दबना बन्द किया, जापान पहले दबता था, उनकी अर्थव्यवस्था ठीक होने के बाद उन्होंने झुकना बन्द किया, यह मलेशिया वगैरह तो पहले से अपने को बचाने की कोशिश में थे, फिर यह हुआ कि अमेरिका इतनी तेजी से नीचे जा रहा था, कि केवल गैर-गोरे देशों का शोषण करने से ही उनकी भूख शान्त होने वाली नहीं थी ।

यूरोप में जनविरोध :

पहले अमेरिका और यूरोप के सारे देश एक गुट में थे, अभी भी हैं, लेकिन (तब) बिल्कुल एकजुट थे । जैसा अमेरिका कहेगी वो यूरोप के देश करेंगे, लेकिन अमेरिका को बचाने के लिए जैसे हम लोगों का शोषण करना आवश्यक उनके लिए था, यूरोप के देशों का भी शोषण करना आवश्यक हो गया । यूरोपीयन कॉम्यूनिटी के 12 देश थे, उनके साथ उन्होंने एक एग्रीमेन्ट किया - किसान और किसानी के बारे में । अब जैसे मैने कहा कि ऊपर के ऊपर एग्रीमेन्ट करते थे, वह पूरा पब्लिश नहीं करते थे मीठा-मीठा, गप-गप इतना ही पब्लिश होता था, इसीलिए किसी ने विरोध नहीं किया । उसका क्रियान्वयन जब शुरू हुआ, अमल जब शुरू हुआ तो एकदम किसानों को लगा कि अरे यह तो हमारे ऊपर आकाश से कुल्हाड़ी गिर गई, उन्होंने विरोध किया और विरोध में आन्दोलन किया यूरोप के किसानों ने । और आन्दोलन में जो उन्होंने मांग रखी जो दुनिया के इतिहास में पहली बार रखी गई थी, मांग रखी कि हमारे सरकारों ने जो हस्ताक्षर किए हैं, समझौते पर, वह हस्ताक्षर वापिस लेने चाहिए । मेरा ख्याल है दुनिया के इतिहास में ऐसी मांग कभी आई नहीं है कि हमारी सरकार ने समझौते पर जो हस्ताक्षर किए हैं वह वापिस लेने चाहिए । (हस्ताक्षर) वापिस तो नहीं लिए लेकिन इस तरह की मांग दुनिया के इतिहास में पहली बार आई ।

उत्तरी अमेरिकी देशों में जनविरोध :

इतना ही नहीं, तो अमेरिका के लोगों का भी शोषण करना इनके लिए बाध्य हो गया, क्योंकि यह बहुत तेजी से अमेरिका नीचे जा रही थी, अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए, तो उन्होंने और एक एग्रीमेन्ट किया, जिसका नाम था - 'नार्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेन्ट', "नाफ्ता" । तीन ही देश आते, मेक्सिको, कनाडा और यूनाईटिड स्टेट्स तो इसमें पहले जब पब्लिश किया, ऐसा ही मीठा-मीठा पब्लिश किया, जब अमल शुरू हुआ तब लोगों को पता चला एकदम असंतोष भड़क गया । अब मेक्सिको के लोग सोफिस्टीकेटेड नहीं है । वो हाथ में राईफल लेकर खड़े हो गए, सेना लाकर उनको दबाया गया, कनाडा में इसके खिलाफ असन्तोष हुआ जब क्रियान्वयन शुरू हुआ, और इतना घोर असंतोष था, और राज्यकर्त्ता दल के दुर्भाग्य से उसी समय इलेक्शन आ गए । तो उस इलेक्शन्स में जिस रूलिंग पार्टी ने इस "नाफ्ता" पर हस्ताक्षर किया था उसको पूरी तरह से उखाड़ फैंक दिया, केवल 2 मेम्बर पार्लियामेन्ट में उनके चुनकर आए । विरोधी दल का उनका राज्य हो गया, और विरोधी दल के प्राइम मिनिस्टर ने पहला पत्र क्लिंटन को लिखा कि हम जानते हैं कि "किसी भी सुशिक्षित, सुसंस्कृत सरकार का यह कर्त्तव्य है कि पुराने सरकारों ने जो अभिवचन दिए हों उनका पालन करना, किन्तु ये जो एग्रीमेन्ट है वो "ऑब्वीयसली अनजस्ट एण्ड अनफेयर ।" स्पष्ट रूप से इतना अन्यायकारक है कि 'आई वांट, आई डिमांड री-नेगोसिएशन ऑन द सेम एग्रीमेन्ट' (इसी एग्रीमेन्ट पर फिर से नेगोसिएशन की मैं मांग करता हूँ।) मेरा खयाल है कि दुनिया के इतिहास में इस तरह की मांग कि जिस एग्रीमेन्ट पर हस्ताक्षर हुए, उस एग्रीमेन्ट पर फिर से नेगोसिएशन हो ऐसी मांग फॉर द फर्स्ट टाइम आई है ।

आम अमरीकी भी त्रस्त

यूनाईटेड स्टेट्स - मैंने आपको बताया कि वहां की गरीब जनता को कुछ पता ही नहीं है कि ऊपर के लोग क्या गड़बड़ कर रहे हैं । तो वहाँ उपभोक्ताओं का एक बड़ा संगठन है जिसके प्रमुख हैं मि. नाडेर । उन्होंने इनके खिलाफ उपभोक्ताओं का आन्दोलन खड़ा किया । वहां के मजदूरों ने इनके खिलाफ आदोलन शुरू किया, क्योंकि इनके योजना के कारण लाखों लोग मजदूरी, नौकरी से हटाए गए,

लाखों परिवार बेघरबार हो गए, तो मजदूरों ने इसका विरोध किया, उपभोक्ताओं ने इसका विरोध किया । और हमको आश्चर्य हुआ कि यह क्या गड़बड़ कर रहे हैं अभी तक वह बताते नहीं थे । किन्तु यह जो गड़बड़ कर रहे हैं इसका उपयोग, गोरे देशों के सामान्य जनता के लिए नहीं है, जैसा मैंने कहा, कि गोरे देशों के राज्यकर्त्ता और गोरे देशों के उद्योगपति, पूंजीपति इनकी सांठगांठ है, सामान्य जनता का इसमें लाभ नहीं है ।

गोरे देशों के आम लोग विरोध में :

धीरे-धीरे गोरे देशों के सब लोगों को जब पता चला, है तो वे गोरे देशों के लोग, सामान्य जनता ने जब ये सारा पढ़ा, तो वहां भी मानवतावादी कुछ लोग है, जो बड़े इंटेलेक्चुअल है, बुद्धिजीवी है, मानवतावादी है, ऐसे लोगों ने एक नया मंच खड़ा किया, जिस मंच का नाम है 'द अदर इकोनोमिक समिट' । और 'द अदर इकोनोमिक समिट' की बैठक उसी जगह, उसी शहर में होती हैं जहाँ उन हरामखोर लोगों की, जी-7 कंट्रीज की हर साल बैठक होती है और इनके खिलाफ रेसोल्यूशन पास किए जाते हैं । पिछले बार दो साल के पहले मैं उधर गया था, डनवर में यह कॉन्फ्रेन्स थी हमको भी बुलाया गया था, तो मैंने देखा साठ लोग थे उतने आवेश के साथ इनके खिलाफ बोल रहे थे, जितने आवेश के साथ हम लोग बोल रहे थे । माने अब उन लोगों में भी जागृति आ गई । और हमने वहाँ यह बताया था, कि हम आपके खिलाफ नहीं है लेकिन हमारा, विकसनशील देशों का, ऐसा ख्याल हो रहा है कि आप सब मिलकर हमारा शोषण कर रहे हैं, तो आपके बारे में मिसअन्डरस्टेंडिंग हमारे देशों में हो रहा है, आप इनका विरोध कीजिए । खैर जो होगा, तो मेरे कहने का मतलब है कि गोरे देशों में भी मानवतावादी लोग इनके खिलाफ हो रहे हैं ।

तो अमेरिका का जो विचार था, कि खटाक से सारा कर देना, कोई सावधान होने के पहले ही सारा हो जाएगा, वैसा नहीं हुआ और विश्व व्यापार संगठन यह संस्था खड़ी हुई । काहे के लिए खड़ी की कुछ निफेरियस डिजाईन (बदनियताना साजिश) इनके जो माने खराब हेतु से जो काम वह करना चाहते हैं, तो उनके

लिए माध्यम के नाते और उसके द्वारा वो सब देशों में अपना साम्राज्य फैलाना चाहते हैं ।

नई पेटेन्ट व्यवस्था - डब्ल्यु. टी. ओ. का हथियार :

अब इसमें पहला उनका है पेटेन्ट का कानून । अभी हमारे सरकार के ऊपर दबाव है कि पेटेन्ट का कानून जैसा उनको चाहिए वैसा हम बदल दें । पेटेन्ट का 1970 का हमारा कानून है, अमेरिका का कानून दूसरे ढ़ंग का है, वो चाहते हैं कि हमारा कानून वैसा बदल जाए । दोनों में अन्तर क्या है समझ लीजिए । एक तो है कि हमारा पेटेंट कानून अच्छा है, ऐसा दुनिया के सब देशों ने कहा था । हमारे कानून में प्लांट्स का पेटेन्ट नहीं है, हर्बल मेडीसिन्स का पेटेन्ट नहीं है, पशुओं का पेटेन्ट नही है, बीजों को पेटेन्ट नहीं है, उनके कानून में सबका पेटेन्ट है ।

और उस पर पेटेन्ट भी जो हमारे देश में है वह प्रोसेस का पेटेन्ट है, प्रोडक्ट का पेटेन्ट नहीं है । माने जैसा च्यवनप्राश गुरूकुल कांगड़ी ने बनाया, तो गुरूकुल कांगड़ी जिस प्रोसेस से च्यवनप्राश बनाती है, उस प्रोसेस का वह पेटेन्ट ले सकती है, लेकिन च्यवनप्राश का पेटेन्ट नहीं होगा । दूसरा कोई दूसरे का से भी च्यवनप्राश बनाता है, तो उसको बनाने का अधिकार है, मार्केट में लाने का अधिकार है । वहाँ प्रोडक्ट का माने आपने एक बार किसी भी प्रोसेस से चीज बना ली, च्यवनप्राश बना लिया, फिर च्यवनप्राश का ही पेटेन्ट है, कोई दूसरे रास्ते से च्यवनप्राश बनाया तो भी उसको मार्केट में लाने का अधिकार नहीं है । अब इसमें वो चाहे जिस बात का पेटेन्ट कर लेंगे । मैंने कहा ना लोगों को अंधेरे में रखना, यह सबसे बड़ी बात है, तो हमारे देश में भी यही हुआ, गैट के बारे में चर्चा हुई, डन्कल के बारे में चर्चा हुई, किन्तु गैट पर जब हमारे लोगों ने हस्ताक्षर किया, सरकार ने पार्लियामेन्ट को अंधेरे में रखकर किया । वैसे 13 दिसम्बर, 1996 को जो सिंगापुर में, इन्होंने दस्तखत किया, कि हम डब्ल्यु. टी. ओ. के मेम्बर बनते हैं । 12 दिसम्बर तक भारत सरकार ने घोषणा की कि हम अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, अमेरिका के सामने नहीं झुकने वाले हैं, 13तारीख को एकदम आत्मसमर्पण कर दिया ।

बिक सकते हैं हमारे नेता - ब्यूरोक्रेट्स :

आप समझ सकते हैं कि यह सारा क्यों होता है, हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि हमारे बड़े-बड़े नेता पर्चेजेबल है, मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ यह स्टेटमेंट कर रहा हूं? कि सेक्रेटरीज तो पर्चेजेबल है ही, नेता और मिनीस्टर भी बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनको विदेशी पूंजी खरीद सकती है । ऐसे पुराने उदाहरण है अब नए क्या होगा, क्या नहीं हम बता नहीं सकते थे, ये केवल पार्टी का सवाल नहीं है, विदेशी पूंजी के हाथ बहुत लम्बे है, कौन खरीदा नहीं जाएगा, यही देखने की बारी हमारे ऊपर आने वाली है ।

तो इस तरह से अब पेटेन्ट का कानून यदि आता है, अब देखिए नीम का उन्होंने पेटेन्ट कर लिया, हल्दी का पेटेन्ट कर लिया, बासमती का पेटेन्ट कर लिया, हमारे लोगों को पता हीं नहीं, अमेरिका में पेटेन्ट कर लिया, हम लोगों को पता ही नहीं । और फिर बताएंगे कि यह हमारा पेटेन्ट है, कोई यहाँ बासमती नहीं लगा सकता, कोई नीम और हल्दी यहाँ नहीं बना सकता, बनाया तो मार्केट में नही ला सकता । क्यों? तो बोलो हमने इसके ऊपर प्रयोग किया है, इसीलिए हमारा पेटेन्ट हो गया. पेटेन्ट यानि एकाधिकार, सर्वाधिकार । अरे नीम पर, हल्दी पर, बासमती पर तुम्हारा अधिकार कैसे हो सकता है? सैकड़ों सालों से हमारे किसानों ने प्रयोग करते हुए और नीम है, हल्दी है, बासमती है, और भी सारे प्लांट्स है, हमारे यहां के औषधि के जो वनस्पतियां है वो वहाँ ले जा रहे हैं, वही परस्पर उनका पेटेन्ट कर रहे हैं, हमको पता ही नहीं और किसानों के लिए उनके हर एक प्लांट का वो पेटेन्ट करना चाहते हैं ।

अब बीजों का पेटेन्ट! :

बीजों का पेटेन्ट इसका मतलब क्या है, कि हमारी कृषि हमारे हाथ में नहीं रहेगी, अमेरिका के हाथ में जाएगी । पेटेन्ट का अर्थ समझ लीजिए कि अभी क्या होता है, उदाहरण के लिए मैं केवल एक बताता हूं, लम्बा बोलना उचित नहीं । जैसे बीजों का पेटेन्ट है, उसका अर्थ क्या होता?

आज हमारे देश के सभी प्रदेशों में ऐसी पद्धति है, कि इस समय की फसल से हर किसान कुछ बीज अगली फसल के लिए बचाकर रखता है और अगले फसल के समय उसी बीज से, अपने ही बीज से वह अगली फसल उगाता है । अब इन्होंने यदि एक बार बीज का पेटेन्ट कर लिया, तो हमारे किसान को अपने बीजों से दूसरी फसल निकालने का अधिकार नहीं रहेगा । अमेरिका से ही बीज लाना पड़ेगा, वो कहेंगे उसी कीमत पर लेना पड़ेगा, अपना बीज बचाकर वह अपनी दूसरी फसल नहीं निकाल सकता, और यदि मानो किसी ने कहा, कि हम तो यहाँ कोने मे पड़े हैं, हमने निकाली तो किसको पता चलेगा, ऐसा नहीं । उनके गुप्तचर रहेंगे सारे देश में, आपने यदि एक कोने में अपने बीजों से अपनी फसल निकाली, वाशिंगटन में रिपोर्ट जाएगा, वाशिंगटन से केवल एक पत्र दिल्ली को आएगा, कि आबूरोड़ के किसानों ने कानूनों का भंग किया है, उनको जेल में डालना चाहिए ।

आरोप लगाना पर्याप्त - अब आरोपित बेगुनाही सिद्ध करे :

अब शुरू से कानून का यह नियम है कि जो आरोप लगाता है उसके ऊपर ओनस होता है, ओनस यानि जिम्मेवारी उसके ऊपर होती है, कि उसका आरोप सही है, वह सिद्ध करे । यह यहाँ उल्टा न्याय ऐसा है, कि वाशिंगटन यदि पत्र लिखता है कि आबूरोड़ के किसानों ने कानून का उलंघन किया । आबूरोड़ के किसानों पर जिम्मेवारी डाली जायेगी कि उन्हें सिद्ध करना चाहिए, कि हमने कानून का भंग नहीं किया । ऐसा कभी दुनिया में कानून बना है पहले । आरोप करने वाले पर आरोप सिद्ध करने की जिम्मेवारी नहीं, जिनके ऊपर आरोप लगाया जाता है उनके ऊपर जिम्मेवारी कि हमने कोई खराब काम नहीं किया ।

स्वदेशी की लड़ाई क्यों? :

तो हमारे बीजों के लिए भी, हमारे पशुओं का भी, चाहे बकरी रहे, भैंस रहे, गाय रहे, बैल रहे, गधा रहे, सबका पेटेन्ट वो कर सकते हैं और फिर उनको रॉयल्टी देकर आप इन पशुओं का उपयोग कर सकते हैं और उद्योगों में तो इतना महान संकट आने वाला है, सभी उद्योगों में वो अपना कब्जा जमाना चाहते हैं । और हमारे यहाँ अभी तक कानून के मुताबिक और सरकार पर दबाव है, कि वह सारे

कानून रद्द कर दे, और ऐसे कानून करे कि हम गोरे देश सीधे आकर उद्योगों को हाथ में ले जाएं । यह सारा यदि हुआ, तो हमारे देश की स्वतंत्रता और सम्प्रभुता (इण्डीपेन्डेन्स और सोवेरेनीटी) क्या रहेगी? इसीलिए यह स्वदेशी का संघर्ष है । माने किसान पूरी तरह से अमेरिका के कब्जे में न जाए, उनके बीज, उनके पशु, उनके प्लांट्स इनका पेटेन्ट वो न कर सके वनस्पतियों के, औषध वनस्पतियों के पेटेन्ट वो न कर सके । फिर हमारे उद्योग गोरे देशों के हाथ में न जाए और इतना यदि गोरे देशों के हाथ में गया तो हमारी स्वतंत्रता का कोई मतलब ही नहीं रहता । इसीलिए स्वदेशी की लड़ाई यह स्वतंत्रता की लड़ाई है, सम्प्रभुता की लड़ाई है । मजदूरों को बचाने के लड़ाई, उद्योगों को बचाने की लड़ाई है, किसानों को बचाने की लड़ाई है । यह समझकर हम सभी लोगों ने जो देशभक्त है उन्होंने स्वतंत्रता, सम्प्रभुता इनको बचाना हमारा कर्त्तव्य है ।

बड़ी मुश्किल के बाद 15 अगस्त, 1947 को हम स्वतंत्र बने, वो जो स्वातंत्र्य आया वह अब हाथ से निकलने वाला है । और यह सारे बातों की जानकारी हमारे नेता जनता को नहीं दे रहे । गोरे देश भी यह चाहते हैं कि आम जनता को आर्थिक बातों का पता न चले, हमारे नेता भी यह जानकारी नहीं दे रहे, और इसीलिए हमने जागृत होकर स्वदेशी का आन्दोलन चलाना चाहिए और अपने देश की स्वतंत्रता, सम्प्रभुता रखना चाहिए, इतना ही कहना इस समय पर्याप्त है ।

किसी ने कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, लेकिन माफ करना भई कि यह विषय ऐसा है, मैं जानता हूं सबके लिए बोर हो सकता है, क्योंकि टैक्नीकल है । पोलिटिकल भाषण में किस्से, कहानियां, चुटकले, विनोदी कथाएँ यह सारा चल सकता है लेकिन इस विषय में यह सब चुटकले वगैरह नहीं चल सकते, तो आपका जरा बोर हुआ होगा, इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ ।

कपटपूर्ण भावना, पर लुभावनी शब्दावली :

अच्छा उनकी एक तरकीब है, वो बड़े-बड़े शब्दों का ऐसा प्रयोग करते हैं, कि अंग्रेजी पढ़े -लिखे लोग उनके जाल में फंस जाते हैं, जैसे, पहले ग्लोबलाईजेशन शब्द आया, लिब्रलाईजेशन शब्द आया, लोगों ने कहा सब अच्छी कल्पना है । हम

पूछते थे भई ग्लोबलाईजेशन क्या है? ग्लोबलाईजेशन के पहले ये तो हम है, जिन्होंने हजारों साल पहले कहा "वसुधैव कुटुम्बकम्”, सारा विश्व ही हमारा परिवार है, इनका ग्लोबलाईजेशन हेजीमोनिसम है । हेजीमोनिसम का मतलब है कि थोड़े देशों का बाकी देशों पर वर्चस्व । तो यह हेजीमोनिसम यानि ग्लोबलाईजेशन, पहले लोग नहीं समझते थे, अब समझने लगे है । किन्तु शब्द ग्लोबलाईजेशन, लिब्रलाईसेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑरगेईजेशन, इसका एक प्रभाव होता है ।

समाधान-मोड़ो तोड़ो या छोड़ो :

अब ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑरगेनाईजेशन के बारे में हमारी जो भूमिका है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि वर्ल्ड ट्रेड ऑरगेनाईजेशन में यदि विकसनशील और विकसित दोनों देशों ने रहना है जैसे आज है, तो दोनों को समान स्टेटस से व्यवहार मिलना चाहिए, दादागीरी नहीं चलनी चाहिए । तो पिछले 3 - 4 नवम्बर, 1997को क्वालालम्पुर में महाथिर मोहम्मद ने एक कॉन्फ्रेंस ली थी, विकसनशील देशों की, जिसको 'जी 15' कॉन्फ्रेंस कहते हैं, उसमें उन्होंने यह रिसोल्यूशन पास किया कि वर्ल्ड ट्रेड ऑरगेनाईजेशन में सबको समान अधिकार होना चाहिए, गोरे देशों की दादागीरी नहीं चलनी चाहिए, और यदि दादागीरी चलायेंगे तो हम वर्ल्ड ट्रेड ऑरगेनाईजेन के बाहर आ जाएंगे । विकसनशील देशों का गुट बनायेंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑरगनाईजेशन में रहे, तो उसके अन्दर रहते हुए विकसनशील देशों का गुट बनायेंगे, बाहर आए तो बाहर आते हुए विकसनशील देशों का गुट बनायेंगे, ये उन्होंने प्रस्ताव पारित किया । स्वदेशी जागरण मंच यही बात बोल रहा है ।

डब्ल्यु. टी. ओ. चुनौती का सामना - मानसिकता का प्रश्न :

लेकिन हमारे अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों के मन में ऐसा प्रभाव है शब्दों का । हमारे यहाँ कहा शब्द मंत्र है, मालूम होता है मंत्र ही है । अब क्या हुआ मेरा विदेश से आने के बाद पांच जगह कुछ अपने ही स्वयंसेवक, इकॉनोमिस्ट इनके साथ चाय पर बैठने का योग आया । अब पहले तीन बैठकों में क्या हुआ कि वर्ल्ड ट्रेड ऑरगनाईजेशन के बारे में चर्चा चली, उससे नुकसान क्या है, फायदा क्या है ।

फायदा एक तो यह है "फेवर्ड नेशन ट्रीटमेन्ट", बाकी सारा नुकसान ही है और फिर अपनी सोवेरनीटी जाती है, सम्प्रभुता जाती है । तीनों बैठकों में ऐसा हाल था, कि वर्ल्ड ट्रेड ऑरगनाईजेशन की जितनी जानकारी मेरे पास थी, उतनी जानकारी उनके पास भी थी । वो भी अर्थशास्त्रज्ञ थे और जब चर्चा होती थी, तो वो सारा बोलते थे, कि भई ये डिस्एडवांटेज है, वो डिस्एडवांटेज है, डिस्एडवान्टेजेज आऊट वे दि एडवान्टेजेज, माने एडवान्टेजेज से बहुत ज्यादा डिस्टएडवान्टेजेज है, सब जानते थे ।

फिर इतना होने के बाद भी जब मैं आखिरी में कहता था कि भई ऐसा यदि है, तो हम बाकी विकसनशील देशों के साथ हम यदि बाहर आ गए तो उसमें आपत्ति क्या है, तो प्रतिक्रिया यह थी, कि वर्ल्ड ट्रेड ऑरगनाईजेशन के बाहर आना माने हम वर्ल्ड ऑरगनाईजेशन के बाहर आयेंगे, अलग- थलग पड़ जायेंगे, माने दुनिया में अकेले रहेंगे, फिर हमारा क्या होगा । तीन जगह अनुभव आने के बाद मैंने यह समझा कि यह प्रश्न समझदारी का नहीं है, साईकोलोजिकल है, मानसिकता का है ।

चौथी जगह ऐसे ही लोग बैठे हमने कहा भई वर्ल्ड ट्रेड ऑरगनाईजेशन इज ए मिसनोमर, इट इज अ वेस्टर्न वर्ल्ड ट्रेड ऑरगनाईजेशन, वेस्टर्न वर्ल्ड के नाते जबरदस्ती हमें बली का बकरा इस नाते हमें घुसेड़ा गया है । तो पांच मिनट में डिस्कशन समाप्त हुआ क्योंकि वो सब जानते थे, जितना मैं जानता था और पांचवे मीटिंग में तो कमाल हो गया, हमने शुरुआत ही यहां से की, कि वर्ल्ड ट्रेड ऑरगेनाईजेशन, इट इस अ वेस्टर्न वर्ल्ड ट्रेड ऑरगनाईजेशन, चर्चा ही बन्द हो गयी, क्योंकि वो सब जानते थे । उन्होंने कहा कि बाहर निकलने में आपति नहीं है, तो शब्दों के प्रभाव में हमारे अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग मानसिक दासता के कारण वो जरा तैयार नहीं होते ।

प्रकाशक : स्वदेशी विचार केन्द्र, जोधपुर प्रान्त सहयोग राशि : पाँच रुपया

देशभक्त अंतर्राष्ट्रीयतावाद के खिलाफ नहीं हैं । राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता का उनका आग्रह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के विरुद्ध नहीं जाता है, बशर्ते उसका आधार समानता हो और उसमें हर देश के स्वाभिमान का सम्मान किया जाए । भूमंडलीकरण के पैरोकारों से उनका विरोध अलग और ज्यादा ठोस सवाल पर है ।

स्वदेशी के आग्रही इस विचार को मानने के लिए तैयार नहीं है कि विकास का पश्चिमी मॉडल सार्वभौम है और दुनियां भर के लोगों को उसकी नकल करनी चाहिए । हालांकि वे सांस्कृतिक आदान-प्रदान को स्वीकारते हैं, मगर इस बात पर जोर देते हैं कि हर समाज की अपनी संस्कृति होती है और हर देश की प्रगति और विकास के मॉडल का उस देश के सांस्कृतिक मूल्यों के साथ तारतम्य होना चाहिए। आधुनिक बनने का मतलब पश्चिमीकरण नहीं है । आधुनिकीकरण के क्रम में राष्ट्रीय संस्कृति की भावना का आदर होना चाहिए । वे पश्चिम के हित में विभिन्न संस्कृतियों और राष्ट्रीय पहचानों को गड्ड-मड्ड कर देने की कोशिशों का विरोध करते हैं ।

आधुनिक पश्चिमी तकनीक और आर्थिक प्रणाली के साथ एक ऐसी सभ्यता आ रही है जो गैर-पश्चिमी सभ्यताओं के अनुकूल नहीं है । विरोध का यह मूल आधार है ।

- **दत्तोपंत ठेंगड़ी**

प्रकाशकीय

निवेदन: प्रस्तुत पुस्तिका में राष्ट्रऋषि परम श्रद्धेय माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी के जोधपुर एवं आबू रोड़ (राजस्थान) में दिए गए दो उद्‌बोधन लेखनीबद्ध हैं। लेख, दिए गए भाषण को यथारूपेण व्यक्त करे इसका पूर्ण प्रयास किया गया है। तथापि भाषण को लेख रूप में प्रस्तुत करने के हेतु से कतिपय परिवर्तन यथा, पुनरावृत्तियों की कमी करना, उप-शीर्षक देना, कुछ शब्दों का भाषान्तर इत्यादि करने पड़े हैं। ज्ञातव्य है कि तथ्यात्मक जानकारी पूर्णत: यथावत रखी गई है। संभव रही त्रुटियों के लिए जिम्मेवारी हमारे प्रकाशन स्तर पर ही है।

- स्वदेशी विचार केन्द्र, जोधपुर प्रान्त।

प्रकाशक

स्वदेशी विचार केन्द्र

96, पत्रकार कॉलोनी, न्यू पॉवर हाउस रोड़, जोधपुर- 342003

दूरभाष : (0291) 2710123